ISSN-0971-8397

विशेषांक

योजना

अगस्त 2023 | विकास को समर्पित मासिक | ₹ 30

समग्र आरोग्यता के लिए एकीकृत दृष्टिकोण
डॉ मनसुख मंडाविया

आज़ादी का अमृत महोत्सव
जी किशन रेड्डी

देश को एकजुट रखने में भारतीय खेलों की भूमिका
अनुराग सिंह ठाकुर

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. Delhi

ELITE IAS

(A PREMIER INSTITUTE FOR CIVIL SERVICES PREPARATION)

ARE YOU DREAMING TO BE AN

IAS ?

CRACK UPSC IN 1ST ATTEMPT NOW

Our Offerings

- Personal Mentorship 1:1 by Subject Expert
- GS Integrated Live Classes
- Exclusive NCERT Coverage
- Intergrated Prelims Cum Mains + Essay Test Series
- Weekly Test, Revision and Personal Guidance
- Online/Offline Sessions

TALK TO US

8410000036, 7065202020, 8899999931

BOOK FREE DEMO SESSION www.eliteias.in

ISSN-0971-8397

विशेषांक

योजना

वर्ष : 67
अंक : 08

अगस्त 2023
श्रावण-भाद्रपद, शक संवत् 1945

मूल्य : ₹ 30
पृष्ठ : 64

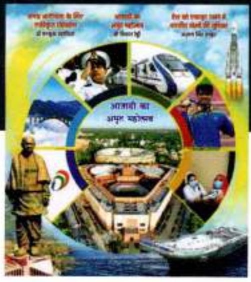

संपादक
डॉ ममता रानी

संपादकीय कार्यालय
648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोदी रोड, नयी दिल्ली-110 003

संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : **डीकेसी हृदयनाथ**

आवरण : **नीरज रिडलान**

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से सम्बन्धित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के व्यक्तिगत हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना लेखकों द्वारा आलेखों के साथ अपने विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र कर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/तालिकाओं/इन्फोग्राफिक्स के सम्बन्ध में उत्तरदायी नहीं है। योजना किसी भी लेख में केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किसी भी ब्रांड या निजी संस्थाओं का समर्थन या प्रचार नहीं करती है।

योजना घर मंगाने, शुल्क में छूट के साथ दरों व प्लान की विस्तृत जानकारी के लिए **पृष्ठ-62** पर देखें।

योजना की सदस्यता शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही योजना प्राप्त न होने की शिकायत करें।

योजना न मिलने की शिकायत या पुराने अंक मंगाने के लिए नीचे दिए गए ई-मेल पर लिखें -
pdjucir@gmail.com

या संपर्क करें-
दूरभाष : 011-24367453
(सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रातः 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)

योजना की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें–
अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोदी रोड,
नयी दिल्ली-110003

इस अंक में...

Elite Academy For Education & Training Pvt. ★ Delhi ★

विहंगावलोकन

6 आज़ादी का अमृत महोत्सव
जी किशन रेड्डी

27 संवहनीय मैनुफैक्चरिंग की ओर छलांग
अंशुमान खन्ना

33 सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल
अनिल सहस्रबुद्धे

37 अटल इनोवेशन मिशन
एक समग्र नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण
प्रमित दाश

45 भारत की जी-20 अध्यक्षता
प्रो हर्ष वी पंत

विशेष आलेख

10 समग्र आरोग्यता के लिए एकीकृत दृष्टिकोण
डॉ मनसुख मंडाविया

16 देश को एकजुट रखने में भारतीय खेलों की भूमिका
अनुराग सिंह ठाकुर

फ़ोकस

23 भारतीय अर्थव्यवस्था
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और आगे का रास्ता
वी अनंत नागेश्वरन

स्थायी स्तंभ

C-3 पुस्तक चर्चा
काला पानी

49 भारत में कृषि
वैश्विक शक्ति बनने की ओर
डॉ जगदीप सक्सेना

53 मीठी क्रांति
शहद उत्पादन में धूम
डॉ शैलेश कुमार मिश्र
डॉ धीरज कुमार तिवारी

57 भारतीय सिनेमा का सफ़र
अमिताव नाग

आगामी अंक : संविधान, सुशासन एवं सुधार

प्रकाशन विभाग के देशभर में स्थित विक्रय केन्द्रों की सूची के लिए देखें पृ.सं. 61

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओड़िया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित।

संपादकीय

जीवन का उत्सव

भारत त्योहारों का देश है। यहां लोग पूरे वर्ष अपनी आस्था, विभिन्न कैलेंडर तिथियों, देवी-देवताओं, महान संतों, लोगों तथा दिनों और क्षेत्रीय रीति-रिवाजों पर आधारित तथा जीवन के सभी पहलुओं के नाम पर असंख्य उत्सव मनाते हैं। ये त्योहार विविधता को दर्शाते हैं और देश भर के लोगों को एक साथ लाते हैं। भारत में बच्चे के जन्म से पहले ही उत्सव और अनुष्ठान शुरू हो जाते हैं। सचमुच, भारत एक ऐसा देश है जहां उत्सव जीवन जीने का एक तरीका है।

इन उत्सवों और भारत की उत्सव भावना को राष्ट्रवादी उत्साह प्रदान करते हुए और सभी भारतीयों को एक सामान्य त्योहार के लिए एक साथ लाते हुए, आज़ादी का अमृत महोत्सव (अकाम) का भव्य उत्सव, 15 अगस्त 2023 को आज़ादी की 75 वीं वर्षगांठ के 75 सप्ताह की उलटी गिनती के साथ 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ। स्वतंत्रता संग्राम, अद्वितीय विचारों, उपलब्धियों, कार्यों और संकल्प पर केंद्रित पांच स्तंभों पर आधारित यह महोत्सव 'जनभागीदारी' की भावना से मनाया गया है। इसने देश की इन 75 वर्षों की उपलब्धियों को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया और अगले 25 वर्षों के लिए संकल्प की रूपरेखा भी दी।

आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें हर घर तिरंगा, वंदे भारतम् नृत्य उत्सव और कलांजलि जैसे कई बड़े कार्यक्रम शामिल हैं। अमृत महोत्सव का उद्देश्य भारत और दुनिया भर में सहयोगात्मक अभियानों और आउटरीच के माध्यम से जन आंदोलन को और बढ़ावा देना है। ये अभियान 'पंच प्राण' के अनुरूप नौ महत्वपूर्ण विषयों की तर्ज पर हैं। ये विषय हैं- महिलाओं, बच्चों तथा जनजातियों का सशक्तीकरण, जल, सांस्कृतिक गौरव, पर्यावरण के लिए जीवन शैली (लाइफ), स्वास्थ्य तथा आरोग्यता, समावेशी विकास, आत्मनिर्भर भारत और एकता।

इस अवधि के दौरान, राष्ट्रीय महत्व के कई स्मारक और संरचनाएं राष्ट्र को समर्पित की गईं, जिनमें प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के माध्यम से आज़ादी के बाद भारत की कहानी दर्शाने वाला 'प्रधानमंत्री संग्रहालय', नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, इंडिया गेट के निकट 'कर्तव्य पथ' और अत्याधुनिक नया संसद भवन शामिल हैं।

प्रत्येक क्षेत्र ने इस उत्सव में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे सहभागी शासन के माध्यम से यह वास्तव में जन-अभियान बन गया। उदाहरण के लिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से और सशक्त बनाने के लिए शुरू किए गए 'महिला सम्मान बचत पत्र' हों या मोटा अनाज तथा योग के माध्यम से सभी के लिए स्वस्थ जीवन शैली विकल्पों को बढ़ावा देना हो या महान स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों का संकलन हो, या फिर जिले की अनूठी विरासतों के डिजिटल जिला भंडार, भारत के लोगों को समर्पित कई अन्य पहल की गई हैं। इन्होंने न केवल भारत को अपनी विकासवादी यात्रा में इतना आगे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि उन्हें 'आत्मनिर्भर भारत' की भावना से प्रेरित 'कर्तव्य काल' और कर्म युग के दृष्टिकोण को सक्षम करने की शक्ति और क्षमता भी दी है।

योजना का यह अंक अतीत में किए गए उन महान कार्यों के लिए सम्मान है जिन्होंने उसकी नींव रखी है जहां हम आज खड़े हैं। विभिन्न क्षेत्रों और पहलों ने भारत की विकास गाथा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये हाल में घोषित कर्तव्य काल - कर्तव्य की अवधि, दृढ़ निश्चय और संकल्प में आगे की राह पर भी प्रकाश डालता है।

आइए, हम दया, करुणा, अच्छाई और समर्पण के अपने छोटे-छोटे तरीकों से इस उद्देश्य में योगदान देने का प्रयास करें। ये उत्सव हमारे जीवन का हिस्सा बना रहें। आइए, हम भारत को आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर स्थान बनाने का संकल्प लें। ❑

उल्लेख है, कार्य@75 में नए भारत की प्रतिबद्धताओं को साकार करने की दिशा में अथक प्रयास उजागर किए जा रहे हैं, संकल्प@75 में निश्चित लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति हमारे संकल्पों की पुष्टि है तथा उपलब्धियां@75 के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति और क्रमिक विकास का प्रदर्शन है।

प्रयास और अभियान

'अकाम' आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अनेक विशेष प्रयास किए गए हैं – 'मेरा गांव मेरी धरोहर' के अंतर्गत देश के 6 लाख 50 हज़ार गांवों का सांस्कृतिक मानचित्र बनाने की योजना है जिसमें प्रत्येक गांव की भौगोलिक, जनसांख्यिकी और सृजनात्मक विशेषताओं का परिचय होगा। गुमनाम नायक पहल के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के कम परिचित, अज्ञात और भूले-बिसरे वीरों का स्मरण करते हुए अकाम की वेबसाइट पर 8 हज़ार 858 गाथाएं प्रकाशित की गयी हैं। डिजिटल जिला भंडार (डीडीआर), जिला इकाई स्तर पर भारत की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े लोगों, घटनाओं और स्थानों का पता लगा कर उनका विवरण संग्रहित करने का प्रयास है। इसके अंतर्गत 11 हज़ार 935 गाथाओं को अकाम की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा रहा है। इस सब की परिणति अकाम के संभवतः सबसे बड़े अभियान 'हर घर तिरंगा' में हुई और देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में लोगों को घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 23 करोड़ से अधिक

हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से जनमानस में एक भारत-श्रेष्ठ भारत की भावना का संचार किया गया है और उन्होंने मिलजुल कर यह महोत्सव मनाया।

स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन से पिछली सहस्त्राब्दी में इस महान देश की नींव डालने वालों को सम्मानित करने के हमारे संकल्प की पुष्टि होती है। वीर बाल दिवस गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबज़ादों बाबा फतेह सिंह और ज़ोरावर सिंह के बलिदान को सम्मानित करने के लिए मनाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनकी परिणति कर्तव्य पथ पर उनकी कांस्य प्रतिमा की स्थापना के साथ हुई। इसी तरह श्री अरबिंदो घोष की 150वीं जयंती, अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती, राजा राम मोहन रॉय की 350वीं जयंती और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर देशभर में बड़े उत्साह के साथ कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री, कई गणमान्य व्यक्तियों और आम लोगों ने भाग लिया।

अभियान 2.0

अकाम के दूसरे चरण में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वाधीनता दिवस पर अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित पंच प्राण से प्रेरित नौ नए विषयों की पहचान की गई है। इनमें महिलाएं और बच्चे, जनजातीय सशक्तीकरण, जल, पर्यावरण के लिए जीवनशैली (लाइफ), स्वास्थ्य और आरोग्य, समावेशी विकास, आत्मनिर्भर भारत, सांस्कृतिक गौरव और एकता शामिल है। ये अभियान मंत्रालयों, विभागों, राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों, गैर-सरकारी संगठनों तथा निजी संगठनों जैसे सभी संबंधित पक्षों के सहयोग से आयोजित किए जा रहे हैं। ये भविष्य के अभियानों का आधार बनेंगे तथा अमृत काल में भारत की वैभवशाली यात्रा का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ❑

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

शब्दों में, ''आरोग्यता के लिए विश्व के लिए भी हमारा दृष्टिकोण वैसा ही है जैसा कि यह अपने देश के लिए है। दुनिया खासकर कोविड-19 के बाद स्वास्थ्य और आरोग्यता को गंभीरता से ले रही है। भारत के पास इस संबंध में देने के लिए बहुत कुछ है। हमारा योग और आयुर्वेद विश्व को स्वस्थ बनाने में योगदान कर सकते हैं।''

किसी राष्ट्र का स्वास्थ्य उसके सभी आयु के लोगों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। राष्ट्र-निर्माण की दिशा में कोई भी प्रयास तभी सफल होता है जब जनता स्वस्थ होती है, जो बदले में स्वस्थ समाज और राष्ट्रीय उत्पादकता में योगदान करती है। देश में राजनीतिक, आर्थिक, जनसांख्यिकीय और महामारी संबंधी परिवर्तनों का लोगों के स्वास्थ्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। परिवर्तनों के साथ लगातार तालमेल बनाये रखने के लिए, नागरिकों के लिए कुशल, न्यायसंगत, सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य नीतियां और मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियां महत्वपूर्ण हैं। इस संबंध में, राष्ट्र एक उत्तरदायी स्वास्थ्य प्रणाली बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है जो उसके नागरिकों को उत्पादक जीवन जीने और स्वस्थ समाज बनाने में सक्षम बनाती है।

भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों के माध्यम से सेवाओं की निरंतरता बनाये रखने के लिए तैयार की गई है। देखभाल के तीनों स्तरों के बीच एक महत्वपूर्ण कार्यात्मक संबंध है, और सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए उनकी अंतर-निर्भरता अपरिहार्य है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), जिसे अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के रूप में जाना जाता है, शुरू में विशेष रूप से कमजोर समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य और संचारी रोगों और एक चयनात्मक प्राथमिक सेवा दृष्टिकोण के साथ चलाया गया था। लाभदायक होने के बावजूद, इसमें कमी यह थी कि यह आबादी की बदलती जरूरतों और गैर-संचारी रोगों के कारण मृत्यु दर तथा रुग्णता के बढ़ते बोझ को संबोधित नहीं कर सका।

आयुष्मान भारत

2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत पहल, जिसमें स्वास्थ्य तथा आरोग्यता केन्द्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) शामिल हैं, स्वास्थ्य सेवा चुनौतियों का समाधान करने और इन सेवाओं की लागत को कम करने में सहायक रही है। आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्यता केन्द्र, समुदाय को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य और आरोग्यता सेवाएं प्रदान करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गरीबों और कमजोर लोगों को अस्पताल में भर्ती और रोगी सेवाएं मुफ्त प्रदान करती है। इन पहल ने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को सफलतापूर्वक लोगों के करीब ला दिया है।

व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं (सीपीएचसी) प्रदान करने और आरोग्यता गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्यता केन्द्र समुदाय के करीब संचालित किये गये। दिसंबर 2022 तक 1.5 लाख आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य और आरोग्यता केन्द्र चालू करके समयबद्ध तरीके से इनका संचालन शुरू करने का इरादा था। इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, राष्ट्र ने सफलतापूर्वक 1,59,859 आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य और आरोग्यता केन्द्रों को समुदाय के करीब लाकर मुफ्त सेवाएं प्रदान कीं और महिलाओं, बच्चों तथा बुजुर्गों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। इन केन्द्रों में शुरुआत के बाद से, 172.13 करोड़ लोगों ने सेवाएं ली हैं, जिनमें मधुमेह के लिए 35.67 करोड़, उच्च रक्तचाप के लिए 41.26 करोड़, ओरल कैंसर के लिए 24.46 करोड़,

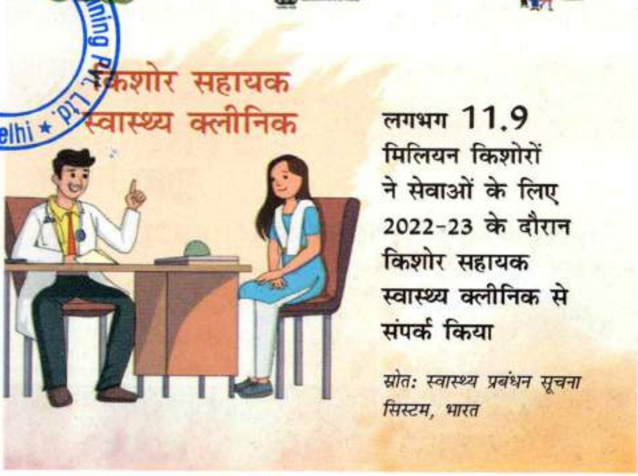

उसके वैश्विक नेतृत्व और लचीलेपन को प्रदर्शित किया। देश ने 2022 तक तेजी से अपनी परीक्षण क्षमता को 3388 प्रयोगशालाओं, 821 सरकारी और 1487 निजी आरटी-पीसीआर प्रयोगशालाओं, 1115 कार्टिज प्रयोगशालाओं और 53 जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशालाओं तक विस्तारित किया। आत्मनिर्भर भारत पहल ने नैदानिक बाजार में प्रतिस्पर्धा की सुविधा प्रदान की और डायग्नोस्टिक वस्तुओं की लागत कम की जो 2020 में 1727 रुपये से घट्कर 2021 में 72 रुपये पर आ गईं। कोविड केन्द्र, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन उत्पादन के लिए पीएसए प्लांट जैसे स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को त्वरित उपलब्ध कराया गया।

महामारी से मिली सीख के आधार पर, देश ने सबसे बड़ी अखिल भारतीय बुनियादी ढांचा योजना - प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन (पीएमएबीएचआईएम) के माध्यम से सेवाओं के स्तर पर एक समग्र स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए 'संपूर्ण समाज' दृष्टिकोण को चुना। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन- बुनियादी ढांचे, निगरानी, निदान, प्रबंधन और अनुसंधान को मजबूत करने के लिए सेवाओं के सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संस्थानों की क्षमताओं में तेजी लाने पर केंद्रित है। मिशन ने अब तक, 7808 भवन-रहित उप-स्वास्थ्य केन्द्रों को सहायता प्रदान की है और 264 से अधिक शहरी स्वास्थ्य तथा आरोग्यता केन्द्रों (यूएचडब्ल्यूसी), 485 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू), 216 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल), और 166 से अधिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) अस्पताल स्थापित किए हैं। विकेन्द्रीकरण की भूमिका पर जोर देते हुए, 15वें वित्त आयोग स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान के माध्यम से ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को 70,051 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन आवंटित किए गए।

G20 | Ministry of Health and Family Welfare, Government of India | PMNCH for Women's, Children's and Adolescents' Health

स्कूल स्वास्थ्य और आरोग्यता कार्यक्रम (एसएचडब्ल्यूपी) के अंतर्गत 34 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में 328 ज़िले

323,000 से अधिक स्वास्थ्य और आरोग्यता एम्बेसडर प्रशिक्षित किए गए

स्रोत: मार्च 2023 तक राज्य रिपोर्ट

देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को विकसित करने और इसमें सहयोग करने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) शुरू किया गया। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों (एबीएचए) के निर्माण के माध्यम से डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में देश की भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है।

लाभों का दोहन करना, कमियों को दूर करना और तैयारियों के लिए नवाचारों तथा सर्वोत्तम प्रथाओं को शुरू करना, परिवर्तनशील और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। आयुष्मान भारत, एक गेम चेंजर के रूप में, सभी स्तरों पर नियमित और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी की सुरक्षा करते हुए, इष्टतम संकट प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों को सुदृढ़ करने के वास्ते एक बहुत जरूरी वर्धक के रूप में सामने आता है। इस प्रकार, जिलों तथा राज्यों को आत्मनिर्भर बनाकर देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाता है।

स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन (एचआरएच)

कुशल स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के महत्व को पहचानते हुए, सरकार ने चिकित्सा और नर्सिंग शिक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा सीटों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। 2014 के बाद से, भारत सरकार द्वारा अपनाई गई प्रमुख कार्यनीतियों के परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में कुशल एचआरएच की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। देश में

सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अवसरों का भी लाभ उठाया जाता हैं और एक अग्रणी वैश्विक क्राउड फंडिंग मॉडल स्थापित किया गया है। हम सब मिलकर प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में टीबी मुक्त भारत की दिशा में काम कर रहे हैं।

मानसिक स्वास्थ्य और आरोग्यता

भारत के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य विकारों के उपचार में 70 से 92 प्रतिशत तक अंतर बताया गया। उपचार अंतर पर प्रकाश डाला। कोविड-19 महामारी के संदर्भ में डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य नेटवर्क की आवश्यकता पर जोर दिया गया। सरकार ने जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की डिजिटल शाखा टेली-मानस की शुरुआत की। 42 स्थापित टेली-मानस सैल के साथ, इस पहल को 1.5 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हो चुकी हैं। गुमनाम सहायता प्रदान करने से व्यक्तियों के अपने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के लिए सहयोग प्राप्त करने को मददगार बताया। इस तरह हम मिलजुल कर, कमियों को दूर कर रहे हैं और इससे संबंधित कलंक से बचने में भी मदद मिलेगा।

नियमित और आपातकालीन दोनों सेवाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की बढ़ी हुई क्षमता, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को दी गई प्राथमिकता का स्पष्ट परिणाम है। पिछले दशक में, प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय में 74 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा में 167 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। वित्त वर्ष 2013-14 के बाद से स्वास्थ्य पर अपनी जेब से खर्च में 16 प्रतिशत अंकों की उल्लेखनीय गिरावट आई है। ये आंकड़े स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने और चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता वाले व्यक्तियों पर वित्तीय बोझ को कम करने के ठोस प्रयासों को प्रदर्शित करते हैं।

पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करती हैं, जो रोकथाम, प्राकृतिक उपचार और मन-शरीर-आत्मा संतुलन पर ध्यान केंद्रित करती हैं। आरोग्यता को बढ़ावा देने में पारंपरिक चिकित्सा की प्रभावशीलता को पहचानते हुए, सरकार ने इन पद्धतियों को मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एकीकृत करने के लिए कदम उठाए हैं।

Academy For Education & Training Pvt. Ltd. Delhi

पारंपरिक औषधियों के लाभों को स्वीकार करना:

पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करती हैं, जो रोकथाम, प्राकृतिक उपचार और मन-शरीर-आत्मा संतुलन पर ध्यान केंद्रित करती हैं। आरोग्यता को बढ़ावा देने में पारंपरिक चिकित्सा की प्रभावशीलता को पहचानते हुए, सरकार ने इन पद्धतियों को मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एकीकृत करने के लिए कदम उठाए हैं। ज्ञान और विशेषज्ञता के इस एकीकरण से मानकीकृत प्रोटोकॉल, साक्ष्य-आधारित दिशानिर्देशों और सुरक्षित तथा प्रभावी पारंपरिक चिकित्सा फॉर्मूलेशन का विकास हुआ है।

भारत में पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने में आयुष मंत्रालय (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए यह एक एकीकृत दृष्टिकोण की सुविधा के लिए एलोपैथिक संस्थानों, अनुसंधान संगठनों और स्वास्थ्य सेवाओं के पेशेवरों के साथ सहयोग करता है। देश भर में आयुष आरोग्य केन्द्रों की स्थापना ने पारंपरिक चिकित्सा को व्यापक आबादी के लिए सुलभ बना दिया है, जो एलोपैथिक स्वास्थ्य सेवाओं की पूरक है।

भारत में पारंपरिक चिकित्सा और एलोपैथी का एकीकरण समग्र आरोग्यता की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम का प्रतीक है। यह सहक्रियात्मक दृष्टिकोण दोनों प्रणालियों की संबंधित शक्तियों को जोड़ता है, रोगियों को व्यापक सेवाएं प्रदान करता है जो उनकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को संबोधित करता है।

भारत की जी20 की अध्यक्षता लोगों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता पर केंद्रित है। लोगों की भागीदारी पर जोर देने वाले जनभागीदारी के मार्गदर्शक सिद्धांत ने पूरे देश में जबरदस्त उत्साह जगाया है। सेमिनार, सम्मेलन और त्योहारों जैसे विविध जी20-संबंधित आयोजनों को भारत की अध्यक्षता में, हितधारकों के रूप में लोगों को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए सोच-समझकर डिजाइन किया गया है।

भारत की जी20 अध्यक्षता की भावना को इसके विषय- 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' में दर्शाया गया है, जो 'वसुधैव कुटुंबकम' के प्राचीन संस्कृत लोकाचार में समाहित है। इसके अनुरूप, समावेशिता को बढ़ावा देने और विकास तथा समृद्धि की यात्रा में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने का मजबूत विश्वास है। हमारी अटूट प्रतिबद्धता प्रत्येक नागरिक के लिए किफायती, न्यायसंगत और सुरक्षित गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है, जो 'सर्वेभवंतुसुखिन:सर्वेसंतुनिरामया:' मंत्र द्वारा निर्देशित है। ❑

पिछले कुछ वर्षों में खेलों के क्षेत्र में भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार आया है। 2020 के टोक्यो ओलिंपिक खेलों में भारत ने एथलेटिक्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने के साथ कुल सात पदक प्राप्त करके अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हमने पैरालिंपिक्स और डेफलिंपिक्स में भी क्रमश: 19 और 17 पदक जीतकर अब तक का सर्वोत्तम प्रदर्शन किया था। फिर, 72 वर्ष में पहली बार थॉमस कप भारत ने जीता और निकहत ज़रीन ने विश्व बॉक्सिंग चैंपियन बनकर देश का गौरव बढ़ाया।

अभी हाल में युवा बैडमिंटन खिलाड़ियों सात्विक और चिराग की जोड़ी ने 1000 इंडोनेशियाई सुपर सीरीज़ में जीत दर्ज करने वाली पहली भारतीय डबल्स टीम बनने का गौरव अर्जित किया और दो दिन के भीतर ही भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी मुकाबलों में भारत के लिए पहली बार कांस्य पदक जीता तथा जूनियर एशियाई कप हॉकी में लड़कों और लड़कियों की टीमों ने एक सप्ताह पहले ही स्वर्ण पदक जीता था-ये सभी उपलब्धियां खेल-जगत में भारत के बढ़ते वर्चस्व को दर्शाती हैं। और, जब भी दुनिया के किसी भी भाग में भारतीय एथलीट पदक जीतता है तो हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाता है।

पदक जीतना और पोडियम पर खड़े होने के साथ ही राष्ट्रगान का बजना समूचे देश को इस प्रकार एक सूत्र में पिरो देता है जैसा साधारणतया अन्य घटनाओं में कम ही होता है।

खेलों की असल खूबी उनसे तुरन्त मिलने वाले परिणाम या कहें सफलता में ही नहीं है, बल्कि इस बात में है कि इनमें समूची पीढ़ी की सोच में बदलाव लाने में है जिसके अंतर्गत युवा अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन करके जीतने का लक्ष्य तय कर लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं कि 'खेलोगे तो खिलोगे।' असल में हार-जीत इतनी ज़रूरी नहीं है जितना युवाओं में खेलने की भावना विकसित करना है क्योंकि खेलों में जीवन के विभिन्न अध्याय इतनी बारीकी से जुड़े हुए हैं कि हमारी भावी पीढ़ी पूरी मेहनत, लगन और निष्ठा के साथ राष्ट्रनिर्माण

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आठ संस्करण हो चुके हैं जिनमें 59,833 प्रतिभागियों के बीच खेलों के माध्यम से सांस्कृतिक आदान-प्रदान हुआ है ।

राष्ट्र निर्माण में सहायक बुनियादी खेल-सुविधाएं

खेलो इंडिया योजना के तहत देशभर में खेलों के लिए बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के प्रयास 2014 के बाद से लगातार किए जा रहे हैं ताकि देश के सभी भागों के युवाओं को खेल के मैदान और प्रशिक्षण केन्द्र उपलब्ध हो सकें। प्रत्येक ज़िले में 1000 खेलो इंडिया सेंटर (केआईसी) बनाने का अभियान देश में खेलों के इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में उल्लेखनीय पड़ाव साबित हुआ था। विभिन्न राज्यों के साथ केन्द्र सरकार की भागीदारी में 31 खेलो इंडिया उत्कृष्टता केन्द्र बनाने की योजना के तहत वरिष्ठ और विशिष्ट एथलीटों को विशेष खेल स्पर्धाओं के लिए प्रशिक्षण की आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

खेल जगत की इन मूलभूत सुविधाओं में 266 खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमी, 500 प्राइवेट (निजी) अकादमी और गोद लिए गए 27 स्कूलों के जुड़ जाने से काफी विस्तार हुआ है और इन अकादमियों में खेलो इंडिया एथलीट ट्रेनिंग लेते हैं। खेलों को कॅरियर बनाने वाले एथलीटों को पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं जिससे देश में खेल संस्कृति का विकास सुनिश्चित हो तथा लगभग 17,500 खेल के मैदान तैयार किए गए हैं जहां अभिभावक अपने बच्चों के लिए अपने घरों के आसपास ही खेलने की जगह ढूंढ सकें।

खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की व्यापक तस्वीर सिर्फ एक आंकड़े से साफ हो जाएगी। 2010 से 2014 के बीच खेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सिर्फ 38 परियोजनाएं पूरी की गई थीं जबकि 2014 से 2023 की अवधि में खेलो इंडिया योजना के तहत कुल 293 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनमें से 146 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। इन बुनियादी सुविधाओं के बन जाने से एथलीटों और खेलों में रुचि रखने वाले लोगों को तो अपने सपने साकार करने में मदद मिली ही है, साथ ही इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में खासी वृद्धि हुई है और अनेकानेक लोगों को रोज़गार भी मिला है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में खेलों की भूमिका वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण रही है।

खेलों में माध्यम से समावेशिता का विकास

खेलों ने विभिन्न क्षेत्रों के खिलाड़ियों और एथलीटों को एक ही जगह पर साथ लाने में अहम भूमिका निभाने के साथ ही आर्थिक और भौगोलिक रूप से बेहद पिछड़े इलाकों की महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने में भी महती योगदान किया है। महिला एथलीटों के लिए खेलो इंडिया महिला लीग आयोजित करने जैसे विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि महिलाओं को खेलों में भाग लेने की प्रेरणा मिले। पिछले वर्ष खेलो इंडिया महिला लीग शुरू होने के बाद से देशभर के 50 शहरों में आयोजित 27 से ज़्यादा खेल स्पर्धाओं में 1.25 लाख से अधिक महिलाएं भाग ले चुकी हैं। वास्तव में खेल जगत से जुड़ी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो दर्शाती हैं कि आर्थिक और सामाजिक बाधाओं से संघर्ष करके महिला एथलीट किस तरह खेलों में अपनी धाक जमाने

खेलों से आर्थिक प्रगति में आती तेज़ी

दूसरा — वित्त वर्ष 2020-21 में दुपहिया साइकिलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और कुल निर्यात 46 करोड़ 10 लाख डॉलर से अधिक

60 प्रतिशत — भारत का खेल सामान बाज़ार 2027 तक बढ़कर 6.6 अरब डॉलर का हो जाने का अनुमान जो 2020-21 में 3.9 अरब डॉलर का था

तीसरा — ज़बरदस्त प्रतियोगी विश्व बाज़ार में एशिया का तीसरा सबसे बड़ा खेल सामग्री बनाने वाला देश

6.6 बिलियन डॉलर — भारतीय कंपनियों में बना 60: खेल सामान निर्यात किया जाता है और उद्योग 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है

दल के खेलों में शामिल होने के लिए 7.7 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की और इन विश्व स्तरीय खेलों की तैयारी के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विशेष प्रशिक्षण शिविर की व्यवस्था की थी। इन खेलों के लिए सरकार की ओर से दी गई आर्थिक सहायता अब तक की सबसे ज़्यादा थी और मुझे विश्वास है कि हमारे ये विशेष एथलीट सर्वाधिक पदक भी जीतकर लाएंगे।

खेलों से मिल रही फिट इंडिया की प्रेरणा

खेल एथलीटों के लिए तो कॅरियर हैं ही, खेल प्रेमियों के लिए भी जुनून से कम नहीं होते। फिर भी, खेल और फिटनेस हर नागरिक की जीवन शैली होनी चाहिए तभी तो वे देश के सर्वांगीण विकास में समुचित योगदान कर पाएंगे। इसी विचार को आधार बनाकर प्रधानमंत्री ने 2019 में फिट इंडिया अभियान की कल्पना की थी ताकि हर नागरिक फिटनेस को अपनी जीवन शैली या दिनचर्या का अंग बना ले और फिटनेस का मंत्र एथलीटों और विशेषज्ञों के लिए ही सीमित न रह जाए।

''फिटनेस की डोज़, आधा घंटा रोज़'' का उनका आह्वान समूचे देश में गूंजा और नागरिकों ने बढ़-चढ़कर मैराथन, साइकिलोथन, दौड़ और अन्य आयोजनों में पूरे वर्ष भर भाग लिया जिससे इसने जनआंदोलन का रूप ले लिया। जहां फिट इंडिया फ्रीडम रन के दो संस्करणों में देशभर के 7.08 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया वहीं स्कूली बच्चों के लिए फिटनेस और खेलों के बारे में आयोजित क्विज़ में 1.74 लाख विद्यार्थियों ने भाग लेने का पंजीकरण कराया जिससे सभी आयु-वर्गों के लोगों में फिटनेस के प्रति बढ़ते आकर्षण और रुचि का पता चलता है। फिट इंडिया इस दृष्टि से अनूठा है कि इससे विद्यार्थियों में फिटनेस और खेलों के महत्व के प्रति जागरुकता पैदा होती है और वे अपने साथियों (समवयस्कों), शिक्षकों और अभिभावकों तक भी इस संदेश को पहुंचाते हैं। विद्यार्थियों को और ज़्यादा प्रेरित करने के उद्देश्य से हर वर्ष फिट इंडिया स्कूल सप्ताह आयोजित किया जाता है और अभी तक 2.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी फिटनेस पर आधारित विभिन्न गतिविधियों में भाग ले चुके हैं। स्कूली विद्यार्थियों से युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों तक सभी आयुवर्गों के लोगों के लिए फिट इंडिया अभियान में शामिल होने से स्पष्ट पता चलता है कि नए भारत को फिट इंडिया बनाने में सभी देशवासी पूरी लगन और संकल्प से जुटे हुए हैं।

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. Delhi

खेलों से आर्थिक वृद्धि में तेज़ी

भारत इस समय विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वह अभूतपूर्व प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आर्थिक प्रगति की इस कहानी में खेल सामग्री बनाने वाले उद्योग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इन्वेस्ट इंडिया की फरवरी, 2023 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अत्यंत स्पर्धात्मक विश्व बाज़ार में खेलों के सामान बनाने के क्षेत्र में भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फिर, भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित खेल सामग्री में से 60 प्रतिशत निर्यात होता है तथा यह उद्योग 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मुहैया कराता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत के निर्यातों में व्यायाम के उपकरण, हवा वाली गेंदें, बाइसिकल, क्रिकेट का सामान, खेल पोशाक इत्यादि शामिल हैं और इनके सहारे ही भारत बड़ा और मज़बूत निर्यातक बन सका है। वह 200 देशों को खेल का सामान निर्यात करता है जिनमें चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। वित्त वर्ष 2022 में भारत दोपहिया साइकिलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया था और उसके कुल निर्यात 46 करोड़ 10 लाख डॉलर से ज्यादा के हुए थे। फिर, खेल सामान निर्यात संवर्द्धन परिषद् की स्थापना जैसे उपायों से भारत के खेल सामग्री निर्माण उद्योग का विस्तार ही होगा। आशा है कि 2027 तक भारत से खेल सामग्री के निर्यात बढ़कर 6.6 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे जबकि 2020-21 में ये निर्यात कुल 3.9 अरब डॉलर के थे। राष्ट्र निर्माण में खेलों की यही अहमियत है।

वास्तव में, पिछले 9 वर्ष में भारत के खेलों का बहुत विकास हुआ है। अब भारतीय एथलीट विभिन्न अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में अपना वर्चस्व बना चुके हैं और खेल जगत में भारत को अब बड़ी ताकत माना जाने लगा है। तभी तो अनेक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय खेल संगठनों ने हाल के वर्षों में भारत को विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं की मेज़बानी के लिए चुना है। 44वें फिडे शतरंज ओलिंपियाड, 2022 में हुए अंडर-17 फीफा विश्वकप, आइबा विश्व बॉक्सिंग प्रतियोगिता और देश के अनेक शहरों में 2023 में आयोजित आईएसएसएफ निशानेबाज़ी विश्व कप भारत के रुतबे को दर्शाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। ❑

भारतीय अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और आगे का रास्ता

राष्ट्रों की प्रगति में उनके विकास-पथ को आकार देने में अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर इसकी अर्थव्यवस्था की यात्रा उन परिवर्तनों, चुनौतियों और अवसरों को दर्शाती है जो भारत की पुष्ट, गतिशील और प्रगतिशील प्रकृति को परिभाषित करते हैं। समय के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, बाधाओं को पार किया है और स्वयं को दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए अवसरों का लाभ उठाया है।

वी अनंत नागेश्वरन | भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार। ईमेल: cea@nic.in

भारत की आर्थिक यात्रा आज़ादी के बाद के शुरुआती वर्षों से प्रारंभ होती है, जब इसने मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया था, जिसमें समाजवादी नीतियों को बाजार अर्थव्यवस्था के घटकों के साथ जोड़ा गया था। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना और आयात प्रतिस्थापन के माध्यम से राष्ट्र-निर्माण, औद्योगीकरण तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इन नीतियों ने हालांकि औद्योगिक विकास की नींव रखी, लेकिन इनसे नौकरशाही की अक्षमताएं, सीमित प्रतिस्पर्धा और अवरुद्ध नवाचार जैसे अनपेक्षित परिणाम भी सामने आए।

1990 का दशक भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था (कुछ लोग सोचते हैं कि इसकी शुरुआत अस्सी के दशक में हुई)। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में देश को व्यापक आर्थिक असंतुलन का सामना करना पड़ा, जिसने सरकार को 1991 में संरचनात्मक सुधार शुरू करने के लिए प्रेरित किया। केन्द्र और राज्य सरकारों के बड़े संयुक्त घाटे, बढती मुद्रास्फीति का दबाव और चालू खाता घाटे ने भुगतान संतुलन संकट की स्थिति पैदा कर दी थी। तब स्थिति पर काबू पाने के लिए भारत ने आर्थिक उदारीकरण और सुधारों की राह पकड़ी।

सरकार ने लाइसेंस राज को खत्म करने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने और निजीकरण को बढ़ावा देने की नीतियां लागू कीं। प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूल्यह्रास की अनुमति देते हुए विनिमय दर को लचीला बनाया गया। चालू खाते पर रुपया पूर्णत: और पूंजी खाते पर आंशिक रूप से परिवर्तनीय हो गया। बाजार-उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर इस बदलाव ने विकास के रास्ते खोले, उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया और वैश्विक निवेश को आकर्षित किया। वास्तविक विकास दर वर्ष 1993 और 2000 के बीच, 1980 के दशक की औसतन 5.5 प्रतिशत से बढ़कर 6.3 प्रतिशत हो गई। विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और वस्तुओं तथा सेवाओं का व्यापार-से-जीडीपी अनुपात 1990 के 17.2 प्रतिशत से बढ़कर 2000 में 30.6 प्रतिशत हो गया।

नई सहस्राब्दी में रुक-रुक कर हुई प्रगति के बावजूद इन सुधारों को जारी रखा गया। 2000 के दशक की शुरुआत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को और अधिक उदार बनाया गया। 1999 की नई दूरसंचार नीति ने भारत में आईटी क्षेत्र में तेजी ला दी, जिससे अन्य क्षेत्रों को भी बड़ा लाभ हुआ। इस अवधि के दौरान इन पहलों के कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित मंत्रालय की स्थापना के साथ, विनिवेश और निजीकरण की नीति ने गति पकड़ी। व्यापक आर्थिक असंतुलन को दूर

कमी, सॉवरेन वैल्थ फंड और पेंशन फंड को कर में छूट, लाभांश वितरण करों से छूट और पूर्वव्यापी कर को समाप्त करने सहित कर नीति में सुधार से व्यक्तियों और व्यवसायों पर कर का बोझ कम हो गया है। जीएसटी के कार्यान्वयन ने कर आधार को व्यापक बनाया है, अनुपालन आवश्यकताओं को कम किया है, राज्य के बाहर माल के मुक्त प्रवाह की सुविधा प्रदान की है और अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में योगदान दिया है। जीएसटी व्यवस्था ने पहले की तुलना में कर संग्रह को बेहतर किया है। जीएसटी का औसत मासिक सकल संग्रह वित्त वर्ष 2018 के 0.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 1.5 लाख करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में 1.7 लाख करोड़ रुपये हो गया है। जीएसटी करदाताओं की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, बड़ी संख्या में छोटे व्यवसाय जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत आ रहे हैं।

लंबे समय से चली आ रही बुनियादी ढांचे की कमियों और लॉजिस्टिक बाधाओं को दूर करने के लिए 2014 के बाद से बड़े पैमाने पर सार्वजनिक खर्च भी किया गया है। केन्द्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.8 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 3.8 प्रतिशत हो गया है। इस निवेश का उद्देश्य सड़क संपर्क (भारतमाला), बंदरगाह बुनियादी ढांचे (सागरमाला), विद्युतीकरण, रेलवे और हवाई अड्डों/हवाई मार्गों (यूडीएएन) जैसे क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार और बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 व्यापक लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करके इन पहलों में सहयोग कर रही है।

भारत जैसे विशाल देश में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए निरंतर और दीर्घकालिक प्रयासों की आवश्यकता को पहचानते हुए, सरकार ने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन (एनआईपी) की स्थापना की है। इस दूरदर्शी दृष्टिकोण वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर 2024-25 तक पांच वर्षों में लगभग 111 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। वर्तमान में, 108 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कुल निवेश के साथ 9,000 से अधिक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन परियोजनाएं विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

इसके अलावा, निवेश माहौल में सुधार के लिए पिछले नौ वर्षों में कई सुधार और पहल की गई हैं। 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य भारत की विनिर्माण क्षमताओं और विभिन्न उद्योगों में निर्यात को बढ़ावा देना है। विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक चैंपियन के रूप में उभरने और घरेलू तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) पेश किए गए हैं। निजी क्षेत्र के लिए व्यावसायिक अवसर बढ़ाने के लिए रक्षा, खनन और अंतरिक्ष सहित रणनीतिक क्षेत्रों को खोल दिया गया है। सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति को और उदार बनाया है, अधिकांश क्षेत्र अब स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खुले हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की

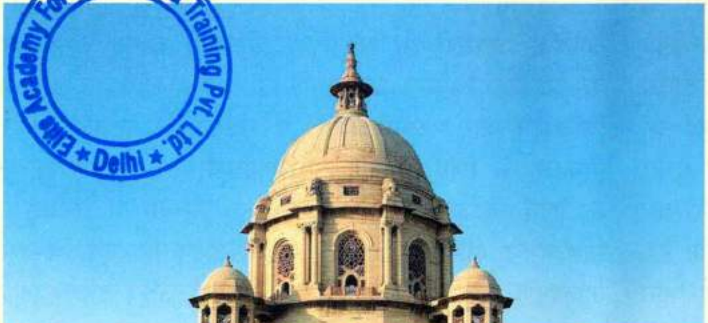

2014 से सरकार की आर्थिक नीति का ध्यान कारोबार सुगमता और भौतिक तथा डिजिटल बुनियादी ढांचे का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार कर भारत की विकास क्षमता को बहाल करने पर रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य समग्र व्यावसायिक माहौल में सुधार करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना है। संचालन व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाते हुए कारोबार सुगमता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विविध आर्थिक सुधार लागू किए गए हैं।

संवहनीय मैनुफैक्चरिंग की ओर छलांग

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★Delhi★

भारत ने पिछले दशक में खास तौर से आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियानों के अंतर्गत अपनी स्वदेशी मैनुफैक्चरिंग की प्रतिस्पर्धिता को मजबूत करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। मैनुफैक्चरिंग में रोजगार पैदा करने की सबसे ज्यादा क्षमता है। इस क्षेत्र में 2030 तक छह करोड़ से सात करोड़ तक रोजगार पैदा हो सकते हैं। मैनुफैक्चरिंग का भविष्य संवहनीयता में बसा है। भारत सरकार जीरो डिफेक्ट-जीरो एफेक्ट और डिजिटल इंडिया जैसी अनेक पहलकदमियों के माध्यम से व्यवसायों को संवहनीय मैनुफैक्चरिंग अपनाने के लिये प्रेरित कर रही है। देश ने पिछले सात वर्षों में अपने नीतिगत और नियामक परिवेश में काफी सुधार किया है। इससे उद्यमों के लिये खुद को स्थापित करना और फलना-फूलना बहुत आसान हो गया है।

अंशुमान खन्ना
सहायक महासचिव, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ (फिक्की)।
ईमेल: anshuman.khanna@ficci.com

स्वतंत्र भारत की 75 वर्षों की यात्रा आसान नहीं रही है। औपनिवेशिक शासकों ने हमारे देश की संपदा को बरबाद कर दिया था। लेकिन आज़ादी के बाद लंबा सफर तय करते हुए भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बन गया है। हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। भारत के लिये यह अपनी क्षमता को पहचानने और कोविड के बाद की नयी वैश्विक व्यवस्था में विश्व गुरु बन कर उभरने का समय है। यह अनिवार्य है कि हम इंसान और पृथ्वी की रक्षा करते हुए संवहनीय और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा दें।

फिक्की-मैकिंजी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 2047 तक उच्च आय वाला राष्ट्र बन जाने की उम्मीद है। उसकी प्रति व्यक्ति आय मौजूदा समय से छह गुना ज्यादा होने और बढ़ते कार्यबल को काम देने के लिये 60 करोड़ रोजगारों

हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे पूंजी के ज्यादा महत्व वाले कुछ क्षेत्रों में भी वैश्विक मूल्य शृंखला से भारत का जुड़ाव अच्छा है।

सरकार ने पीएलआई के लिये विविध क्षेत्रों को चुना है। मोबाइल फोन, एसीसी बैटरी, उच्च क्षमता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, ड्रोन, वियरेबल, सेमीकंडक्टर और विशिष्ट इस्पात जैसे नये जमाने के अनेक क्षेत्रों में यह योजना शुरू की गयी है। सरकार से मिलने वाले प्रोत्साहनों का एक बड़ा हिस्सा नये जमाने के इन क्षेत्रों के लिये है। ये नये युग के क्षेत्र भारत को मैनुफैक्चरिंग के केन्द्र के रूप में प्रमुखता दिलाने में मददगार होंगे। इन प्रयासों के नतीजे दिखायी देने लगे हैं। भारत में 2014 में मोबाइल फोन की सिर्फ दो फैक्टरियां थीं। लेकिन इस क्षेत्र को नीतिगत समर्थन दिये जाने के परिणामस्वरूप अब हम मोबाइल फोन का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गये हैं। मौजूदा समय में भारत 11 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा के मोबाइल फोन का निर्यात करता है। मोबाइल उपकरणों के वैश्विक बाजार में भारत एक प्रमुख निर्यातक के तौर पर उभरा है। देश से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में पांचवां सबसे बड़ा हिस्सा मोबाइल फोन का है।

मैनुफैक्चरिंग का भविष्य संवहनीयता में बसा है। ग्राहकों को वैसे उत्पादों और साझीदारों की तलाश है जो संवहनीयता के लिये प्रतिबद्धता में हिस्सेदारी करते हुए पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं और हरित नीतियों का पालन करें। वित्तीय लाभों और वैश्विक प्रतिस्पर्धिता के लिये भी संवहनीयता महत्वपूर्ण है। इसलिये भी उत्पादकों को संवहनीयता की दिशा में कदम उठाते हुए इसे अपनी रणनीति और संचालन के प्रमुख लक्ष्य में शामिल करना चाहिए।

हमारा लक्ष्य मुंबई-ठाणे-रायगढ़ क्लस्टर की तरह क्लस्टरों को बंदरगाह के नजदीक विकसित कर इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और चिकित्सा उपकरण जैसी पांच से छह विशिष्ट वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भारत की मौजूदगी बढ़ाने का होना चाहिए। राज्य सरकारें अपनी मैनुफैक्चरिंग क्षमताओं के अनुरूप सभी सुविधाओं से लैस क्लस्टर क्षेत्रों की स्थापना कर इन प्रयासों में सहायक बन सकती हैं। मसलन, सरकार के सड़क विकास कार्यक्रम भारतमाला के अंतर्गत अनेक शहरों में बहुविध लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित किये जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और वैमानिकी में नागपुर की तरह मैनुफैक्चरिंग के लिये विश्व स्तरीय और कार्यकुशल लॉजिस्टिक्स क्षेत्र बन सकते हैं। सोलापुर कपड़ा और सिलेसिलाये वस्त्रों का केन्द्र बन सकता है। इसके अलावा क्षमता उपयोग को 80 प्रतिशत से ज्यादा करने के लिये अनुबंध उत्पादन, नवोन्मेष अनुदान जैसे आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम तथा सिंगल विंडो मंजूरी से इन विशिष्ट वैश्विक मूल्यशृंखलाओं में भारत की मौजूदगी बढ़ सकती है।

मैनुफैक्चरिंग में डिजिटल क्रांति का अंगीकरण

राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनी संघ (नैसकॉम) की हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मैनुफैक्चरिंग उद्योग ने वित्त वर्ष 2021 में उद्योग 4.0 समाधानों पर 5.5 से 6.5 अमेरिकी डॉलर तक की रकम खर्च की। सरकार के नियम और निजी क्षेत्र के निवेश भारतीय मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र को डिजिटल प्रौद्योगिकी अपनाने के लिये प्रेरित कर रहे हैं। छोटे, मझोले और बड़े मैनुफैक्चरिंग उपक्रम अपने व्यवसाय के कुछ या सभी स्तरों पर डिजिटलीकरण के लिये वस्तु इंटरनेट, कृत्रिम मेधा, बिग डाटा वैश्लेषिकी और रोबोटिक्स जैसी 4.0 प्रौद्योगिकियों के उपयोग से उत्पादन के नये प्रतिमान विकसित कर सकते हैं। इससे वे इस नयी औद्योगिक क्रांति की अग्रिम कतार में शामिल हो सकेंगे।

डिजिटलीकरण से विश्वसनीयता और मूल्य शृंखला के लचीलेपन में सुधार हो सकता है। मसलन, दूरमापन जैसी उन्नत वैश्लेषिकी का उपयोग कर उत्पादक अपने डिलीवरी नेटवर्कों का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। इससे वे भंडारण और वितरक के स्तर पर मांग का बेहतर ढंग से अनुमान भी लगा सकेंगे। प्रौद्योगिकी अनुदान और अंतरराष्ट्रीय संयुक्त उपक्रमों से प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञता हासिल करने में सहायता मिलेगी जो मैनुफैक्चरिंग को डिजिटल भविष्य में ले जाने में मददगार होगी। स्मार्ट मैनुफैक्चरिंग में 5 जी की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उद्योग 4.0 के लिये 5 जी के इस्तेमाल के क्षेत्रों में संयोजित संपदा निगरानी, संबद्ध भंडारगृह, अनुमान आधारित रखरखाव, लॉजिस्टिक्स और फ्लीट मैनेजमेंट तथा गुणवत्ता प्रबंधन शामिल हैं।

मैनुफैक्चरिंग उद्योगों की सहायता के लिये प्रौद्योगिकीय विकास पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र की प्रौद्योगिकीय प्रगति के लिये सही कौशलों और क्षमताओं वाला कार्यबल भी आवश्यक है। मैनुफैक्चरिंग एमएसएमई के भविष्योन्मुख होने के लिये कौशल विकास और उन्नयन में सहयोग देना वक्त की जरूरत है। भारत को कौशलों में असमानता को खत्म करने के लिये ठोस कौशल विकास कार्यक्रमों में ज्यादा निवेश करना होगा। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिये शैक्षिक संस्थानों और उद्योग संस्थाओं के बीच

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. * Delhi *

सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सभी के लिए सुलभ, न्यायसंगत और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कई व्यापक सुधारों की परिकल्पना की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की शक्ति के साथ ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी, एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) जैसे नए उपायों के बल पर गुणवत्ता में वृद्धि हुई है और शिक्षार्थियों ने बेहतर महसूस किया है।

अनिल सहस्रबुद्धे | अध्यक्ष, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, नई दिल्ली। ईमेल: chairman-netf@gov.in

प्रौद्योगिकी से 17वीं सदी से ही उद्योग 1.0 से लेकर उद्योग 4.0 तक, भाप इंजन के आविष्कार से लेकर अंतरिक्ष शटल तक, टेलीफोन से मोबाइल तक, इंटरनेट और 2जी से 5जी तक, और पीसी से सुपर कंप्यूटर तक हमारे जीवन में क्रांति आई है। तकनीकी परिवर्तन की रफ्तार चौंकाने वाली है और इसे बनाये रखना कठिन होता जा रहा है। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन न केवल आवास, पानी, स्वच्छता, ऊर्जा स्रोत, संचार, परिवहन इत्यादि जैसे हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में हैं, बल्कि महत्वपूर्ण रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और कृषि में भी हैं। ब्लैकबोर्ड और चॉक, पेंसिल, पेन और कागज से लेकर ओवरहेड प्रोजेक्टर, एलसीडी, पीसी, लैपटॉप, सीडी, डीवीडी और टीवी से लेकर स्मार्ट व्हाइट बोर्ड, इंटरनेट, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और एमओओसी प्लेटफार्मों ने दरवाजे पर शिक्षा को संभव बना दिया है, जिससे शिक्षा की डिलीवरी में बदलाव हुए हैं। शिक्षा आज किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी डिवाइस पर उपलब्ध है। पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के लिए अनेक विकल्पों के बीच कई बार चयन करना कठिन हो जाता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल) की शक्ति के साथ ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर), वर्चुअल रियलिटी (वीआर), एक्सटेंडेड रियलिटी (एक्सआर), एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) जैसे नए उपायों, और चैटजीपीटी ने गुणवत्ता को बढ़ाया है और शिक्षार्थियों का अनुभव बेहतर हुआ है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे 29 जुलाई, 2020 को लागू किया गया था, सभी के लिए सुलभ, न्यायसंगत और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कई व्यापक सुधारों की परिकल्पना की गई है। इसमें स्कूली शिक्षा में जीईआर को शत-प्रतिशत और उच्च शिक्षा में 50 प्रतिशत करना शामिल है। इसे केवल स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की इमारतों के माध्यम से हासिल करना मुश्किल है। यह तभी संभव है जब प्रौद्योगिकी और इसका इस्तेमाल हो, जो खाई को पाटने में सक्षम बनाएगा और पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके अलावा, सरकार के दृष्टिकोण से, यह निवेश पर अत्यधिक लाभदायक (आरओआई) होने के साथ-साथ किफायती भी है।

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★Delhi★

राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रयास राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के माध्यम से चल रहे थे, वहीं दूसरी ओर, राज्य स्तर, विश्वविद्यालय स्तर और यहां तक कि कॉलेज स्तर पर कई उत्साही लोगों द्वारा ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म (एलएमएस) बनाने या संलग्न करने के प्रयास किए गए, जिससे व्यक्तिगत या स्वास्थ्य समस्याओं के कारण छूटी हुई कक्षाओं वाले लोगों के लिए शिक्षा सुलभ हो सके। मुक्त शिक्षा संसाधनों (ओईआर) का प्रसार और दुनिया भर में उनकी निःशुल्क उपलब्धता और अधिक सशक्त बना रही है।

कारगर शिक्षण और सीखने हेतु शिक्षक प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और कई राज्य स्तरीय टियर-2 और टियर-3 कॉलेजों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी एक बड़ी बाधा रही है। भौतिक मोड में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संस्थान से छुट्टी, यात्रा और आवास लागत के संदर्भ में सीमाएं थीं। कुछ महिला शिक्षकों और संकाय सदस्यों को परिवार और छोटे बच्चों के प्रति समर्पण के कारण बाहर न जा पाने की अतिरिक्त समस्याएं थीं। ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से अमृता विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया एक सरल ए-व्यू प्लेटफॉर्म एक बड़ी सफलता थी। प्रौद्योगिकी और इंटरनेट की उपलब्धता की बदौलत आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी खड़गपुर द्वारा संचालित टी10केटी कार्यक्रम को बड़ी संख्या में संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित करने में भारी सफलता मिली, जिनमें से कई महिलाएं थीं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के अटल अकादमी कार्यक्रम, जिसमें 1.5 लाख फैकल्टी को एआई, एमएल, रोबोटिक्स, ड्रोन, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा एनालिटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उच्च-स्तरीय उभरती प्रौद्योगिकियों में साल-दर-साल प्रशिक्षित किया जाना, सफलता की एक और गाथा है। एआईसीटीई ने 8 फैकल्टी इंडक्शन मॉड्यूल भी बनाये, जो इंजीनियरिंग, शिक्षण अध्यापन, पाठ्यक्रम विकास, प्रौद्योगिकी के उपयोग, परीक्षा पेपर सेटिंग, अनुसंधान, नवाचार और संस्थान प्रशासन की भूमिका से शुरू होकर युवा प्रेरक शिक्षकों को सशक्त बनाते हैं।

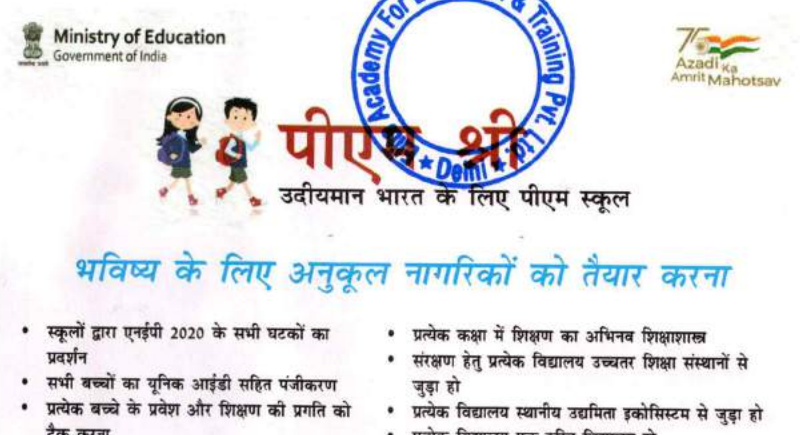

जब ये बदलाव हो रहे थे, 2011 में पहला एमओओसी (मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स) अस्तित्व में आया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोरसेरा, एमआईटी से ईडीएक्स और कई अन्य लोकप्रिय हो गए। भारत कहीं पीछे ना रहे, इसलिए इसने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से वित्त पोषण के साथ एआईसीटीई के माध्यम से अपना स्वयं का स्वदेशी एमओओसी प्लेटफॉर्म, स्वयम बनाया। आज, आईआईटीएम द्वारा बनाये गए इस उन्नत स्वयम 2.0 एमओओसी में न केवल देश के कोने-कोने से बल्कि कई विकासशील देशों से 3000 से अधिक पाठ्यक्रम और 3 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। कला, वाणिज्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रबंधन से संबंधित पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध हैं। इससे छात्र और भी सशक्त हुए हैं।

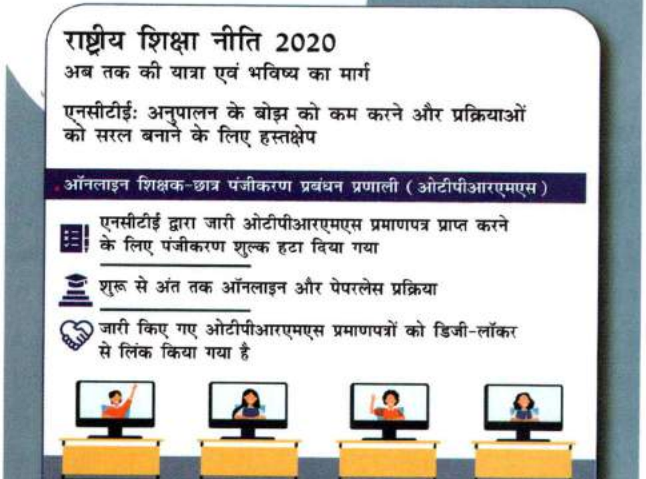

छात्रों की नियोजननीयता अक्सर उद्योग निकायों द्वारा उठाया जाने वाला मुद्दा रहा है। व्यावहारिक अनुभव, अनुभवात्मक

अटल इनोवेशन मिशन
एक समग्र नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण

नवाचार आदिकाल से ही मानव विकास की आधारशिला रहा है। अग्नि की खोज से लेकर उसे नियंत्रित करने, पहिए के आविष्कार और इसके असंख्य उपयोगों तक नवाचार ने प्रागैतिहासिक काल से प्रगतिशील परिवर्तनों को जन्म दिया है।

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. * Delhi *

प्रमित दाश
कार्यक्रम निदेशक, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग।
ईमेल: pramitdash.aim@govcontractor.in

"भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका इसे बनाना है" – अज्ञात

औद्योगिक क्रांति के साथ और विशेषकर विगत शताब्दी में नवाचार का गहरा असर स्पष्ट तौर पर देखा गया है। इससे दुनिया भर में प्रौद्योगिकी में असाधारण बदलावों और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। इसने न केवल बढ़ती आबादी की जरूरतों और अपेक्षाओं की पूर्ति की है बल्कि हमारे जीवन को बेहतर, अधिक संयोजित और दिनोंदिन समृद्ध भी बनाया है।

लेकिन वास्तव में नवाचार क्या है?

नवाचार महत्वपूर्ण मसलों के नए समाधान प्रदान करके उनके महत्त्व को बढाने की प्रक्रिया है। यह किसी आविष्कार या स्थापित प्रौद्योगिकी के लिए नए अनुप्रयोगों का सृजन है।

पारंपरिक जीडीपी अनुमानों के अनुसार 1700 ईस्वी तक दुनिया की वास्तविक जीडीपी 0.1 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम की दर से बढ़ी क्योंकि यह केवल जनसंख्या वृद्धि के कारण उपभोग वृद्धि से जुड़ी थी। विश्व सकल घरेलू उत्पाद में जबरदस्त वृद्धि 1750 के दशक के बाद शुरू हुई। इस बदलाव का श्रेय औद्योगिक क्रांति के दौरान प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों के आगमन को दिया जा सकता है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण 18वीं शताब्दी में भाप इंजन प्रौद्योगिकी का विकास है। इसने छोटे और अधिक कुशल इंजनों के निर्माण को सक्षम बनाया जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ और वस्तुओं और लोगों के परिवहन में क्रांति का दौर आ गया।

है और इसमें नवाचार की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को शामिल किया जाना चाहिए। एआईएम ने अपने दायित्व को पूरा करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। इसने ऐसे कार्यक्रम, नीतियां और संस्थान विकसित किए हैं जिनमें स्कूली छात्रों से लेकर स्थापित स्टार्ट-अप तक विचार-विमर्श से लेकर विनियोजन तक का पूरा परिदृश्य शामिल होता है। हस्तक्षेपों की यह निरंतरता यह सुनिश्चित करती है कि सहायता के अभाव के कारण कोई नवप्रवर्तक अपने मार्ग से न भटके।

प्रारंभिक चरण में युवाओं के चिंतन में नवाचार के बीज बोए जाते हैं। इस दौरान स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) बच्चों के बीच टिंकरिंग की अवधारणा को बढ़ावा देती है जो चीजों को समझने और बनाने के दौरान समस्या-समाधान, नवीन मानसिकता को प्रेरित करती है।

थोड़े बाद के चरण में जब ये युवा कॉलेज में प्रवेश करते हैं और अपने विचारों को अवधारणाओं और स्टार्ट-अप में विकसित करना चाहते हैं तो उच्च शिक्षा या अनुसंधान संस्थानों में स्थापित अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (एआईसी) सभी आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र सहायता और पोषण देने के लिए तैयार होते हैं ठीक वैसे ही जैसे एक इनक्यूबेटर शिशुओं के साथ करता है। प्रमुख शहरों में नवाचार के सामान्य समूहों से आगे बढ़ने और व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों और सूक्ष्म उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए टियर-2 और टियर-3 शहरों में अटल सामुदायिक नवाचार केन्द्र (एसीआईसी) नवाचार को भौगोलिक और भाषाई रूप से समावेशी बनाते हैं। अटल न्यू इंडिया चैलेंज (एएनआईसी) कार्यक्रम के माध्यम से एआईएम राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता की क्षेत्रीय चुनौतियों को हल करने के लिए काम करने वाले स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई को परिकल्पना से लेकर व्यावसायीकरण तक सीधे वित्त पोषित करता है।

आइए अटल इनोवेशन मिशन के कार्यक्रम स्तंभों को समझा जाए:

एआईएम के कई स्तंभ हैं जिनके माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। पिछले वर्षों में एआईएम ने नवप्रवर्तकों को उनके नवाचार के जीवन-चक्र में सहायता देने और भारत की नवाचार यात्रा में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल), अटल इनक्यूबेशन सेंटर्स (एआईसी), अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स (एसीआईसी), अटल न्यू इंडिया चैलेंज (एएनआईसी), और मेंटर ऑफ चेंज की शुरुआत की।

मेंटर इंडिया एआईएम द्वारा पूरे भारत में स्थापित 10,000+ अटल टिंकरिंग लैब्स में छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए मार्गदर्शकों (परिवर्तन के सलाहकार) को चुनने की स्वैच्छिक पहल है जो युक्तिपूर्ण राष्ट्र-निर्माण में योगदान करती है।

अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल)

'भारत में दस लाख बच्चों को नियोटेरिक इनोवेटर्स के रूप में तैयार करने' की दृष्टि से, एआईएम ने पूरे भारत के स्कूलों में एटीएल की स्थापना की है। एटीएल छठी से 12वीं कक्षा के युवाओं में जिज्ञासा और नवाचार को बढ़ावा देने और समस्या-समाधान, नवोन्मेषी मानसिकता को प्रोत्साहित करने के लिए एक अत्याधुनिक मंच है। एटीएल में 21वीं सदी के उपकरण और प्रौद्योगिकियां जैसे कि आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग टूल, रोबोटिक्स, लघुरुपी इलेक्ट्रॉनिक्स, डीआइवाई (डू इट योरसेल्फ) किट आदि होते हैं। यहां युवा प्रायोगिक और स्वयं करें गतिविधियों (डू इट योरसेल्फ) के माध्यम से अपने विचारों को आकार दे सकते हैं।

एटीएल एक ऐसा स्थान प्रदान करते हैं जहां छात्र 'तोड़-फोड़-जोड़' के विचार के साथ सृजन करते हैं - यानी यहां उन्हें नवाचार करते हुए सृजन करने की स्वतंत्रता मिलती है। 21वीं सदी के कौशल के लिए छात्रों की क्षमता निर्माण के लिए एटीएल समय-समय पर कई पाठ्यक्रम और मॉड्यूल जारी करता है। एटीएल की प्रमुख पहल एटीएल मैराथन और टिंकरप्रेन्योर छात्रों को उत्पाद बनाने और उन्हें युवा उद्योगपति के रूप में दुनिया के सामने आने के लिए एक मंच प्रदान करता है। सर्वश्रेष्ठ छात्रों को 'स्टूडेंट इनोवेटर प्रोग्राम' के माध्यम से उद्योग से जुड़ने और अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है जिसके अंतर्गत वे विभिन्न उद्योग विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में अपनी परियोजनाओं को आगे विकसित करते हैं और उन्हें अधिक बाजारोपयोगी बनाते हैं। एटीएल का लक्ष्य भविष्य के नवप्रवर्तकों के लिए आवश्यक कौशल सेट प्रदान करना है।

आज 35 से अधिक राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में फैले देश के 700 से अधिक जिलों के 10,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स हैं। इनमें से 60 प्रतिशत एटीएल सरकारी स्कूलों में हैं और 75 लाख से अधिक छात्रों को कवर करते हैं जिन्होंने 12 लाख से अधिक नवाचार परियोजनाएं बनाई हैं।

अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (एआईसी)

एआईएम 2017 से अटल इनक्यूबेशन सेंटर नामक इनक्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना में सहायता कर रहा है ताकि मापनीय और टिकाऊ उद्यम बनने की दिशा में अग्रसर नूतन स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा दिया जा सके। एआईसी देश भर में मौजूद विश्व स्तरीय इनक्यूबेशन केन्द्र हैं जिनमें पूंजीगत संपत्ति और परिचालन सुविधाओं से युक्त उपयुक्त बुनियादी ढांचे के साथ-साथ स्टार्ट-अप

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

परिवर्तन के सलाहकार (एमओसी)

मेंटर इंडिया एआईएम द्वारा पूरे भारत में स्थापित 10,000+ अटल टिंकरिंग लैब्स में छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए मार्गदर्शकों (परिवर्तन के सलाहकार) को चुनने की स्वैच्छिक पहल है जो युक्तिपूर्ण राष्ट्र-निर्माण में योगदान करती है।

आज देश भर में 6,000 से अधिक मेंटर युवा चिंतन को पोषित करने की एआईएम की आकांक्षा में मददगार सिद्ध हो रहे हैं। उद्योग और शिक्षा जगत के ये सलाहकार एक या अधिक ऐसी प्रयोगशालाओं में नियमित रूप से अपना समय देते हैं और छात्रों को डिज़ाइन और कम्प्यूटेशनल सोच, तर्कसंगत रूप से सोचने और विचारों के बीच तार्किक संबंध को समझने की क्षमता जैसे भविष्य के कौशल का अनुभव करने, सीखने और अभ्यास करने और कक्षाओं में जो उन्होंने सीखा है उसे व्यावहारिक स्थिति में लागू करने में सक्षम बनाते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में एआईएम ने बहुत से युवा टिंकरर्स और स्टार्ट-अप्स की सहायता की है जो अपने प्रदेश और क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान खोजने के लिए उन्मुख हुए हैं।

नवीन हस्तक्षेपों की इस निरंतरता के माध्यम से एआईएम मानसिकता में परिवर्तन और एक सांस्कृतिक बदलाव ला रहा है जिससे भारत 'आत्मनिर्भरता' की ओर अग्रसर होगा।

केस स्टडी

क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हर दिन 'नो हॉर्न डे' हो तो माहौल कितना शांतिपूर्ण होगा?

कल्पना कीजिए कि पीक आवर्स में लाल बत्ती और ट्रैफिक जाम के बीच वाहन सड़क पर चल रहे होंगे लेकिन कानफाड़ू हॉर्न नहीं होंगे। हालांकि, सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं लेकिन नागरिकों ने इस दिशा में सीमित प्रयास किए हैं। परन्तु राजस्थान के एक 18 वर्षीय छात्र ने इस समस्या का समाधान निकालने का बीड़ा उठाया।

यह छात्र अन्वेषक जो अभी बीटेक की पढ़ाई कर रहा है ध्वनि प्रदूषण के समाधान खोजने पर काम करने के प्रति इतना संकल्पबद्ध था कि उसने इससे निपटने के लिए एक उपकरण बनाया। उन्होंने व्हीकल हॉर्न कंट्रोल असेंबली (वीएचसीए) पर काम किया जो कुछ क्षेत्रों में हॉर्न बजने को रोकता है और हॉर्न-निषिद्ध क्षेत्रों में इसकी तीव्रता को भी घटाता है। वीएचसीए एक अत्याधुनिक प्रणाली है जो वाहनों के हॉर्न से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को पूरी तरह से नियंत्रित करने में मदद करती है। यह नवाचार सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 11: टिकाऊ शहरों और समुदायों को लक्षित करता है। नवाचार पेटेंट कराया गया है और ऐसे समाधान प्रदान करता है जो लागत-कुशल और मापनीय हैं। ध्वनि प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को काफी हद तक कम करने के लिए ऑटोमोबाइल विनिर्माण

NITI Aayog | ATAL INNOVATION MISSION

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

TINKERPRENEUR 2023

स्पॉटिफाई पर
13 क्षेत्रीय भाषाओं
में टिंकरप्रेन्योर
पॉडकास्ट सुनें

G20 वसुधैव कुटुंबकम्
Azadi Ka Amrit Mahotsav

भारत 2023

भारत के प्रांतों, केंद्रशासित प्रदेशों, भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों तथा नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की आधिकारिक जानकारी देने वाला वार्षिक संदर्भ ग्रंथ

ऑर्डर के लिए संपर्क करें :
फोन : 011-24367260
ई-मेल : businesswng@gmail.com
हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड नई दिल्ली -110003
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

सूचना भवन की पुस्तक दीर्घा में पधारें

@publicationsdivision @DPD_India @dpd_India

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

भारत की जी-20 अध्यक्षता

वैश्विक व्यवस्था में अग्रणी स्थान बनाने की चाहत रखने वाले देश के रूप में भारत जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्यसेवा और प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों से संबंधित विश्व की अहम चुनौतियों को अपने नेतृत्व के माध्यम से सुलझाने के लिये गंभीर है। वह जी-20 की अपनी अध्यक्षता में एक ज्यादा न्यायसंगत विश्व के निर्माण के लिये प्रयासरत है। जी-20 शासन की वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा और उनके समाधान के लिये विकसित और विकासशील देशों को एकजुट करने वाला एक अनूठा मंच है। भारत प्रमुख वैश्विक मसलों पर सहमति कायम कर विभाजन को प्रभावी ढंग से मिटा सकता है।

Academy For Education Training Pvt. Ltd. Delhi

प्रो हर्ष वी पंत | उपाध्यक्ष, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, अध्ययन और विदेश नीति। ईमेल: harshpant@orfonline.org

भारत ने जी-20 की अध्यक्षता वैसे समय में संभाली जब विश्व में उथल-पुथल का माहौल था। लेकिन हमारे देश के लिये यह एक सुअवसर भी था। भारत की आर्थिक विकास गाथा परवान चढ़ रही थी। वह ब्रिटेन को पीछे छोड़ विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरा है। जी-20 विश्व के 80 प्रतिशत से ज्यादा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), 75 प्रतिशत व्यापार और 60 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। उसके लिये यह अनेक चुनौतियों के बीच अपनी प्रासंगिकता को रेखांकित करने का समय है। अनिश्चित वैश्विक परिवेश और नयी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की शुरुआत के बीच भारत की विश्वसनीयता अपने सर्वोच्च स्तर पर है। उदीयमान आर्थिक शक्ति होने के साथ ही वह वैश्विक बहुपक्षवाद पर अपनी प्रतिबद्धता के जरिये कानून के शासन तथा विश्व शांति और सुरक्षा के संवर्द्धन के लिये कृतसंकल्प है। वैश्विक जनकल्याण की उसकी क्षमता का विकास हो रहा है। भारत कोविड-19 की वैश्विक महामारी के

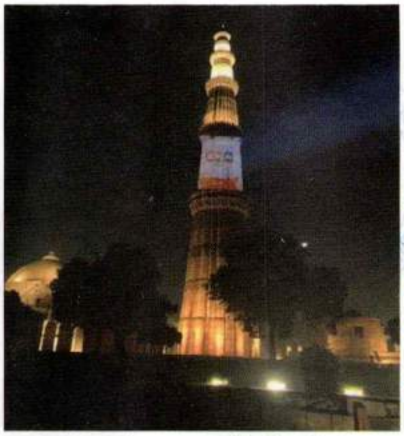
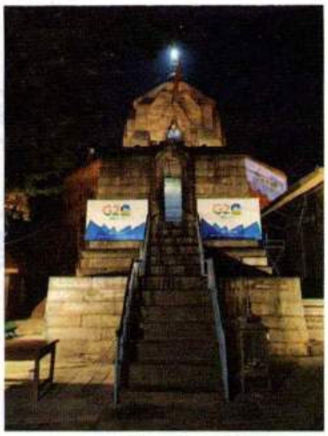

अपनी अध्यक्षता को सिर्फ कूटनीतिक ही नहीं, बल्कि जन भागीदारी की ऐतिहासिक घटना बनाना है। विदेश मंत्रालय ने भी ऐसी ही भावना व्यक्त करते हुए जी-20 को वास्तविकता में जनसमूह बनाने के भारत के लक्ष्य को दोहराया। भारत ने जी-20 में जन भागीदारी की अपनी परिकल्पना के तहत विभिन्न नागरिक गतिविधियों का आयोजन किया है। उसने 50 शहरों में 32 कार्यशाखाओं में 200 से ज्यादा बैठकों की मेजबानी की है। इस सहभागी कूटनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रांतों और क्षेत्रों को प्राथमिकता देना तथा उन संस्कृतियों का प्रदर्शन करना है जिन पर पहले पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

इक्कीसवीं सदी की जटिल चुनौतियों की वजह से वैश्विक सहयोग के पारंपरिक मॉडल तनाव में हैं। वैश्विक व्यवस्था में अग्रणी स्थान बनाने की चाहत रखने वाले देश के रूप में भारत जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्यसेवा और प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों से संबंधित विश्व की अहम चुनौतियों को अपने नेतृत्व के माध्यम से सुलझाने के लिये गंभीर है। भारत विकासशील देशों की चिंताओं को ऐतिहासिक रूप से बहुपक्षीय मंचों पर उठाता रहा है। जी-20 की अध्यक्षता ने भारत को वैश्विक मंच पर अपने बढ़ते रसूख को प्रदर्शित करने का एक नया जरिया प्रदान किया है। उसने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, उद्यमिता और नवोन्मेष, जलवायु न्याय तथा किफायती स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच जैसे उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं के लिये महत्वपूर्ण मसलों को जोरशोर से उठाया है।

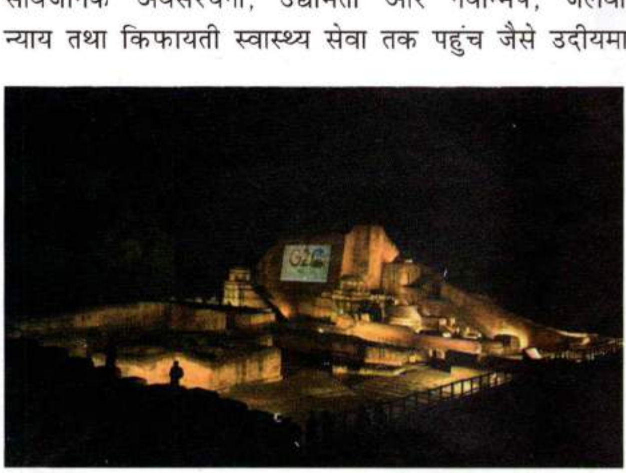

लेकिन भारत की जी-20 की अध्यक्षता चुनौतियों से मुक्त नहीं है। समूह की बड़ी ताकतों के बीच बढ़ते तनावों और बहुपक्षीय संस्थाओं की विश्वसनीयता के संकट ने राष्ट्रों को एकजुट करना ज्यादा मुश्किल बना दिया है। भारत को उम्मीद है कि वह विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर प्रमुख हितधारकों को एकजुट करने और बहुपक्षवाद में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की विश्वास बहाली में कामयाब होगा। यह निश्चित तौर पर मुश्किल काम है। लेकिन भारत के कूटनीतिक प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया है कि उसकी जी-20 की अध्यक्षता वैश्विक शासन पर विमर्श को आगे बढ़ा सके। यह कहना सर्वथा उचित होगा कि भारत की जी-20 की अध्यक्षता ने अव्यवस्था और अवरोध की ओर बढ़ रही एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को कुछ हद तक व्यवस्थित किया है।

मौजूदा समय में विश्व भर के राष्ट्र निजी हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। आतंकवाद, महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसी बहुराष्ट्रीय चुनौतियां ज्यादा सहयोग की मांग करती हैं। लेकिन वे स्वार्थ पर आधारित अस्थाई गठजोड़ करने में लगे हैं। मगर भारत ने बहुपक्षीय मंचों की चुनौतियों से निपटने की क्षमता में दुनिया के विश्वास को बहाल करने का प्रयास किया है। जी-20 विकसित और विकासशील देशों को एक जगह लाने वाला एक दिलचस्प मंच है। कोई भी दूसरा मंच इन दोनों समूहों को इस तरह एक साथ नहीं लाता। जी-20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत का लक्ष्य विश्व को एकजुटता की बेहतर समझ की ओर ले जाने का है। भारत का बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र होना विभिन्न हितधारकों को वैश्विक चुनौतियों के बारे में सोचने और उनसे मुकाबले के लिये एकजुट होने पर प्रेरित करने में सहायक हो सकता है। 75 साल का भारत, वैश्विक मंच पर एक महत्वाकांक्षी भूमिका निभाने के लिये अच्छी स्थिति में है। जी-20 की अध्यक्षता ने एक भरोसेमंद वैश्विक वार्ताकार के रूप में उसकी विश्वसनीयता को पुष्ट किया है। ❑

भारत में कृषि वैश्विक शक्ति बनने की ओर

भूख और गरीबी से जूझते हुए, देश ने विकास के लिए अपनी पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) का मसौदा तैयार किया, जिसमें कृषि उत्पादन बढ़ाने और भूख को खत्म करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। परिणामस्वरूप, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार का ध्यान कृषि से औद्योगिक विकास की ओर स्थानांतरित करने के लिए बढ़ावा मिला। आज, भारत कृषि के वैश्विक क्षेत्र में कई सराहनीय स्थितियों से गुजर चुका है। उल्लेखनीय है कि भारत का खाद्यान्न उत्पादन इसकी जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो गया है। आत्मनिर्भरता से उठकर भारतीय कृषि अब कृषि की वैश्विक शक्ति बनने की ओर आगे बढ़ रही है।

डॉ जगदीप सक्सेना
पूर्व मुख्य संपादक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
ईमेल: jagdeepsaxena@yahoo.com

पिछले 75 वर्षों में, भारतीय कृषि ने परिवर्तन की एक उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण सफलता की कहानी लिखी है। आज़ादी के समय खाद्य वस्तुओं की भारी कमी से शुरुआत करते हुए, अब हम कृषि-निर्यात की बढ़ती प्रवृत्ति के साथ एक गौरवान्वित खाद्य अधिशेष राष्ट्र हैं। पीछे मुड़कर देखें, तो भारत को विनाशकारी बंगाल अकाल (वर्ष 1943-44) की छाया में आज़ादी मिली, जिसमें लगभग 30 लाख लोग कुपोषण या बीमारी के कारण मारे गए। भारत की जनसंख्या तीव्र खाद्यान्न की कमी, लगातार सूखे और अकाल का सामना कर रही थी और व्यापक कुपोषण से पीड़ित थी। हालांकि लगभग 85 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती थी और अपनी आजीविका कृषि से प्राप्त करती थी, लेकिन देश में खाद्यान्न की बेहद कमी थी, जिसका मुख्य कारण खेती के प्रति अंग्रेज़ सरकार की प्रतिकूल नीतियां थीं। वर्ष 1950-51 के दौरान, भारत में केवल 50.82 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, जो बढ़ती आबादी को पर्याप्त रूप से खिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था और संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं से खाद्यान्न मांगने के लिए भारत मजबूर हुआ। वर्ष 1948, 1962 और 1965 में लगातार युद्धों के साथ-साथ बार-बार पड़ने वाले सूखे ने स्थिति को और भी खराब कर दिया। इस गंभीर परिदृश्य ने देश को एक अप्रत्याशित 'जहाज़ से मुंह तक' के अस्तित्व में धकेल दिया और भारत को 'बेग्गिंग बाउल' या 'भीख का कटोरा' राष्ट्र के रूप में भी बदनाम किया। लाखों भारतीयों को भूख से बचाने के लिए

मिशन शुरू करके तिलहन पर विशेष जोर दिया गया। नवीनतम फसल उत्पादन तकनीकों को शुरू करने और नए क्षेत्रों में अपने खेतों का विस्तार करके तिलहन उत्पादन में सफलता हासिल की गई। परिणामस्वरूप, तिलहन उत्पादन वर्ष 1985-86 में 108.30 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 400 लाख मीट्रिक टन हो गया। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2020-21 तक उत्पादन की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत रही। रबी 2020-21 के दौरान शुरू किए गए विशेष सरसों कार्यक्रम का सबसे शानदार परिणाम आया। सरसों के उत्पादन में 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 91.24 से बढ़कर 128.18 लाख टन हो गई, और उत्पादकता में 11 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो 1331 से 1447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। रेपसीड और सरसों का क्षेत्रफल 29 प्रतिशत बढ़ा, जो वर्ष 2019-20 में 68.56 लाख हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2020-23 में 88.58 लाख हेक्टेयर हो गया। तिलहन उत्पादन में भारी उछाल को भारत में कृषि के इतिहास में अक्सर 'पीली क्रांति के रूप में जाना जाता है।

उल्लेखनीय है कि भारत का खाद्यान्न उत्पादन इसकी जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो गया है। वर्ष 1951 से 2022 तक, खाद्यान्न उत्पादन में प्रति वर्ष 2.61 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर दर्ज की गई, जबकि जनसंख्या वृद्धि दर 1.95 प्रतिशत रही। जबकि अनाज का उत्पादन लगभग सात गुना बढ़ गया है, इसी अवधि के दौरान दालों का उत्पादन 3.25 गुना बढ़ा है। खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता वर्ष 1951 में 395 ग्राम से बढ़कर वर्ष 2022 में 514.5 ग्राम हो गई है। बागवानी फसलों (60 प्रतिशत सब्जियां, 31 प्रतिशत ताजे फल) का उत्पादन हाल ही में खाद्यान्न के उत्पादन से आगे निकल गया है, और देश की पोषण सुरक्षा को एक मजबूत योगदान दे रहा है। खाद्य अधिशेष राष्ट्र होने के नाते, सरकार किसानों और 'कृषि उद्यमियों' के हित में कृषि-निर्यात को बढ़ावा दे रही है। परिणामस्वरूप, कृषि और संबद्ध निर्यात वर्ष 2020-21 में 41.86 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 50.24 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है, यानी लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि। 'अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष' (2023) मनाते हुए, भारत मोटा अनाज के लिए एक अंतरराष्ट्रीय केन्द्र बनने के लिए तैयार है, जिसे हाल ही में 'श्री अन्न' नाम दिया गया है। इसकी विभिन्न प्रचार रणनीतियों ने वर्ष 2022-23 में इसका उत्पादन 159 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ा दिया है, जबकि सरकार ने वर्ष 2023-24 में 170 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। कोविड-19 महामारी के दौरान, भारतीय कृषि ने रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन करके अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिससे देश महामारी प्रभावित गरीब देशों को भोजन की आपूर्ति करने में सक्षम हुआ।

विभिन्न क्रांतियों की बौछार

हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बीच कई समानताएं हैं, दोनों ने क्रमशः खाद्यान्न और दूध में आत्मनिर्भरता लाने में मौलिक भूमिका निभाई है। खाद्यान्नों की तरह, आज़ादी के समय भारत दूध की उपलब्धता से भी जूझ रहा था, जिसका उत्पादन उस समय मात्र 17 मिलियन मीट्रिक टन था। जैसे-जैसे हमारी आबादी बढ़ी, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में गिरावट आई, जिससे देश दूध संकट में और फंस गया। सरकार ने मेट्रो शहरों में डेयरी योजनाएं स्थापित की थीं, लेकिन उनकी आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा दूध पाउडर के वाणिज्यिक आयात से पूरा किया गया था। हालांकि, सरदार वल्लभभाई पटेल की सलाह पर स्थापित एक सफल दुग्ध सहकारी समिति आणंद, गुजरात में काम कर रही थी। वर्ष 1964 में, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की स्थापना की गई, जिसके प्रमुख डॉ वर्गीस कुरियन थे। एनडीडीबी ने भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्ष 1970 के दशक के दौरान एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, ऑपरेशन फ्लड (ओएफ) शुरू किया। ओएफ कार्यक्रम ने दूध के संग्रह, प्रसंस्करण और विपणन के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचे के साथ ग्राम-स्तरीय दुग्ध सहकारी समितियों का एक नेटवर्क बनाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। इसने आधुनिक तरल दूध प्रसंस्करण संयंत्रों की शुरुआत की और दूध को अधिशेष से कमी वाले क्षेत्रों में ले जाने के लिए एक राष्ट्रीय दूध ग्रिड बनाया। आंदोलन ने जल्द ही गति पकड़ ली और बहुत तेजी से दूध उत्पादन संतोषजनक स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 1976 तक, दूध का नियमित वाणिज्यिक आयात बंद हो गया था। तब से, भारत ने दूध उत्पादन के मामले में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

मीठी क्रांति

शहद उत्पादन में धूम

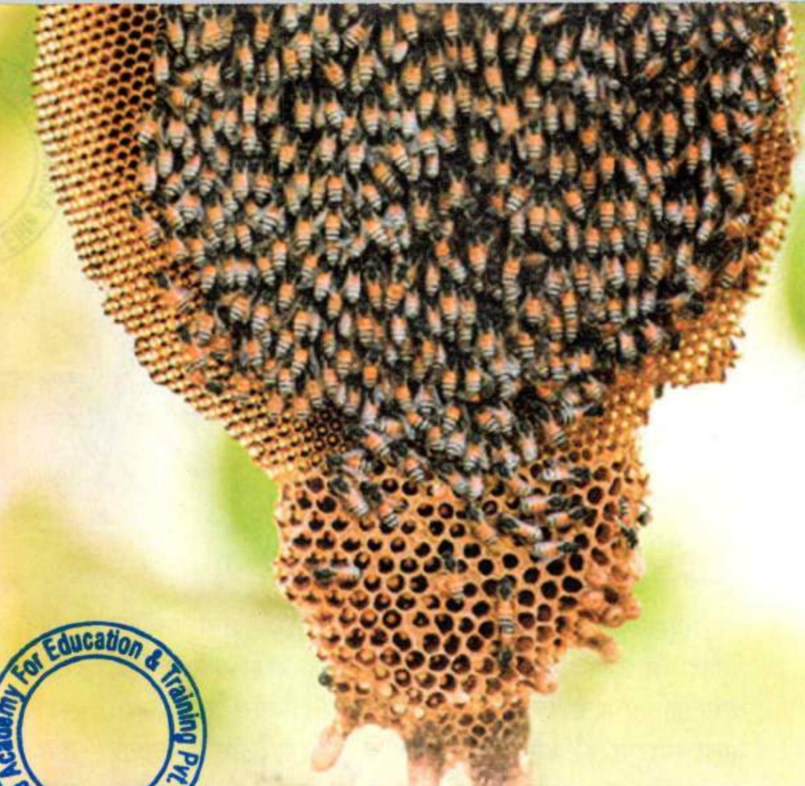

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★Delhi★

मीठी क्रांति या स्वीट रिवोल्यूशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शहद और अन्य संबंधित उत्पादों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना है। मधुमक्खी पालन एक कम निवेश और अत्यधिक कुशल उद्यम मॉडल है, जिसमें प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरा है। मीठी क्रांति को बूस्टर शॉट प्रदान करने और मिशन मोड में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास के लिए सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन शुरू किया।

डॉ शैलेश कुमार मिश्र | निदेशक (विस्तार), विस्तार निदेशालय, कृषि भवन, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ईमेल: shaileshk.mishra29@gov.in

डॉ धीरज कुमार तिवारी | वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केन्द्र (आईसीएआर), उन्नाव। ईमेल: dk9hau@gmail.com

भारत ने कृषि आधारित सहायक व्यवसाय के रूप में मधुमक्खी पालन की अनुकरणीय तीव्र गति से वृद्धि देखी है। भारत में मधुमक्खी पालन पहाड़ों, तलहटी, जंगलों, कृषि भूमि, मैंग्रोव वनों आदि में किया जाता है। मधुमक्खी पालन में शामिल तकनीक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। मुख्य फसल एपिस डोरस्टा, एपिस सेराना और एपिस मेलिफेरा से होती है। एपिस मेलिफ़ेरा को भारत के उत्तरी और पूर्वी मैदानी इलाकों में सफलतापूर्वक पेश किया गया था। देश में विशिष्ट स्थानों के लिए प्रबंधन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम विकसित हुए हैं। वनस्पति और जलवायु की बदलती परिस्थितियों के संदर्भ में जोर दिया गया है। प्रत्येक कृषि-जलवायु क्षेत्र के लिए मौसमी प्रबंधन के अलावा, कॉलोनी उत्पादकता और शहद, मोम, पराग, रॉयल जेली, आदि के उत्पादन में सुधार के लिए उपयुक्त प्रबंधन प्रौद्योगिकियों को अपनाया गया है। आज, भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत मधुमक्खी पालन एक महत्वपूर्ण, टिकाऊ और अभिन्न कृषि गतिविधि है क्योंकि यह पोषण, आर्थिक और पारिस्थितिक सुरक्षा और संतुलन प्रदान करता है। कृषि-जलवायु परिस्थितियों, विविध वनस्पतियों, फसल के बदलते कृषि/बागवानी पैटर्न, मधुमक्खियों के प्रकार, प्रबंधन प्रथाओं आदि का ज्ञान देश में मधुमक्खी पालन उद्योग को

संभावित स्वास्थ्य लाभ भी हैं और यह कई घरेलू उपचारों और वैकल्पिक चिकित्सा उपचारों में भूमिका निभाता है। स्वादिष्ट होने के अलावा, अन्य तरीकों से भी कच्चा शहद सभी के लिए अच्छा है। मधुमक्खी पालन एक महत्वपूर्ण टिकाऊ और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल गतिविधि है; इसमें वानिकी, सामाजिक वानिकी और कृषि सहायक गतिविधियों का एकीकरण शामिल है क्योंकि यह रोजगार और आय प्रदान करते हुए पोषण, आर्थिक और पारिस्थितिक संतुलन प्रदान करता है। शहद उत्पादन एक स्थायी आय स्रोत प्रदान करता है, जिसमें केवल कम लागत वाले निवेश और प्राकृतिक संसाधन आधार का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। शहद सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले मिठास में से एक है, जिसके अत्यधिक स्वास्थ्य लाभ हैं। इसके अलावा, इसका उपयोग दुनिया भर में कई संस्कृतियों द्वारा कई पारंपरिक दवाओं, खासकर आयुर्वेद के आधार के रूप में किया जाता है।

मधुमक्खी पालन के विकास को सुविधाजनक बनाने वाले प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों को दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, भारत के गंगा के मैदान और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है।

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. Delhi

मीठी क्रांति

मीठी क्रांति या स्वीट रिवोल्यूशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शहद और अन्य संबंधित उत्पादों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना है। मधुमक्खी पालन एक कम निवेश और अत्यधिक कुशल उद्यम मॉडल है, जिसमें प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरा है। पिछले कुछ वर्षों में अच्छी गुणवत्ता वाले शहद की मांग बढ़ी है क्योंकि इसे प्राकृतिक रूप से पौष्टिक उत्पाद माना जाता है। अन्य एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन संबंधी उत्पाद जैसे रॉयल जेली, मोम, पराग आदि का भी दवा निर्माण, भोजन, पेय पदार्थ, सौंदर्य और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी पालन को बढ़ाने से किसानों की आय बढ़ेगी, रोजगार पैदा होगा, खाद्य सुरक्षा और मधुमक्खी संरक्षण सुनिश्चित होगा और फसल उत्पादकता और परागण में वृद्धि होगी। मधुर क्रांति को बूस्टर शॉट प्रदान करने के लिए, सरकार ने एक लक्ष्य की तरह वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन शुरू किया।

सरकारी पहल

प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर 2017 को आमेरली (गुजरात) में एक किसान सभा का आह्वान किया, इसका उद्देश्य श्वेत और हरित क्रांति की तर्ज पर देश में 'मीठी क्रांति' लाने के लिए बड़े पैमाने पर शहद की खेती शुरू करना है। मधुमक्खी पालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए और 'मीठी क्रांति' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी पालन के समग्र विकास की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास और गुणवत्तापूर्ण शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों के उत्पादन के लिए एक नई केन्द्रीय क्षेत्र योजना राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह योजना राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र योजना (भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित) के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी) का मुख्य उद्देश्य भारत में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देकर परागण के माध्यम से फसलों की उत्पादकता बढ़ाना और मधुमक्खी पालकों/किसानों की आय बढ़ाने के लिए शहद उत्पादन में वृद्धि करके मधुमक्खी पालन का समग्र विकास करना है।

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) में निम्नलिखित उप-योजनाएं/तीन लघु मिशन हैं-

1. **मिनी मिशन-I:** इस मिशन के तहत, वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को अपनाकर परागण के माध्यम से विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार पर जोर दिया जाएगा;
2. **मिनी मिशन-II:** यह मिशन इन गतिविधियों के लिए अपेक्षित ढांचागत सुविधाओं को विकसित करने पर जोर देने के साथ संग्रह, प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, मूल्य संवर्धन इत्यादि सहित मधुमक्खी पालन/मधुमक्खी उत्पादों के कटाई के बाद प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा; और
3. **मिनी मिशन-III:** यह मिशन विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों/कृषि-जलवायु और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के लिए अनुसंधान और प्रौद्योगिकी उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करेगा।

देश में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास के लिए एनबीएचएम मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने से संबंधित अन्य सरकारी कार्यक्रम/योजना, जैसे एमआईडीएच

भारतीय सिनेमा का सफ़र

Elite Academy For Education & Training Pvt. ★ Delhi ★

भारतीय सिनेमा में मुख्यधारा की फ़िल्मों पर शुरूआत से ही भरत मुनि के 'नाट्यशास्त्र' की भारतीय नाट्य परंपरा का अत्यधिक प्रभाव रहा है। 40 के दशक की शुरूआत में अपने प्रसार के बल पर ही हिंदी सिनेमा ने 'भारतीय' सिनेमा के सबसे बड़े प्रतिनिधि के रूप में स्थापित होने लगा। सत्यजीत रे की बांग्ला फ़िल्म पाथेर पंचाली भारतीय सिनेमा की आज तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक फ़िल्म है। 1950 के दशक में यकायक कई भारतीय फ़िल्मों का प्रवेश विदेशी फ़िल्मोत्सव में होने लगा। इनमें भारतीय फ़िल्मों को काफी सराहा गया और यह सिलसिला 1957 में चरम पर पहुंच गया। 1951 में गठित एस के पाटिल फ़िल्मों जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर फ़िल्म निर्माण में कलात्मक प्रतिभा विकसित करने के लिए 1960 में फ़िल्म वित्त निगम (बाद में फ़िल्म विकास निगम) का गठन किया गया। तब से साढ़े सात दशक बाद भारतीय सिनेमा जहां वह नई प्रोद्यौगिकी को अपनाकर फिर से खड़ा है और ओटीटी प्लेटफॉर्म की खोज करता है।

अमिताव नाग
स्वतंत्र फ़िल्म आलोचक, सिलहट पत्रिका के एक संस्थापक सदस्य एवं उसके वर्तमान संपादक।
ईमेल: amitava.nag@gmail.com

22 मार्च 1985 को मानव इतिहास में पहली बार फ़िल्म प्रदर्शित की गयी। पेरिस में ल्यूकमिरे बन्धुओं ऑगस्तेफ और लुइस ने एक फ़िल्म 'ला सोर्टी दि आई यूसीन ल्यूमिरे अ ल्योशन' को गिने-चुने दर्शकों के सामने निजी रूप से प्रदर्शित किया। दोनों भाइयों ने उसी वर्ष 28 दिसंबर को 10 लघु फ़िल्मों का व्यावसायिक प्रदर्शन किया। यह फ़िल्में दुनियाभर में घूमीं और छह महीने के भीतर 'सिनेमा' भारत पहुंच गया। फ़िल्मों को सबसे पहले तत्कालीन बम्बई में और फिर कलकत्ता और मद्रास में दिखाया गया। बड़े शहरों में भारतीय फ़िल्म उद्योग पल्लवित हुआ। 1913 में पहली फीचर फ़िल्म 'राजा हरिश्चंद्र' आई। अपेक्षानुरूप यह एक मूक फ़िल्म थी जिसे दादा साहब फाल्के ने बनाया था। उसके बाद से भारतीय सिनेमा ने तेज़ी से उड़ान भरी और 1931 में अर्देशिर ईरानी की फ़िल्म 'आलम आरा' से बोलती फ़िल्मों का शुभारंभ हुआ।

माध्यम की सीमाओं की अधिक समझबूझ की आवश्यकता है... हमारे सिनेमा को सबसे ज्यादा ज़रूरत ऐसी शैली और मुहावरे की, सिनेमा के ऐसे निराले अंदाज़ की है, जिस पर विशिष्ट भारतीयता की छाप हो।'' रे ने चिदानंद दासगुप्ता, आर पी गुप्ता, हरिसाधन दासगुप्ता जैसे अपने मित्रों के साथ मिलकर एक साल पहले कलकत्ता फ़िल्म सोसाइटी की स्थापना की थी। यह फीचर फ़िल्मों के लिए भारत की पहली फ़िल्म सोसायटी थी, हालांकि वृत्तचित्र फ़िल्म निर्माताओं ने भी 1942 में बम्बई में फ़िल्म सोसायटी की स्थापना की थी। अगले तीन दशकों में, कला रूप में सिनेमा पर चर्चा करने और दर्शकों को इसकी क्षमता एवं रचनात्मक संभावनाओं से अवगत कराने के उद्देश्य से देशभर में फ़िल्म सोसायटियां स्थापित की गईं। दुर्भाग्यवश इनमें से अधिकांश सोसायटियों की चर्चाएं, भारतीय फ़िल्मों को नजरअंदाज कर विदेशी भाषा की फ़िल्मों तक सीमित हो जाने से उन्होंने अपनी प्रासंगिकता खो दी।

चेतन आनंद की 'नीचा नगर' और ख्वाजा अहमद अब्बास की 'धरती के लाल', दोनों ही 1946 में बनीं थीं। उनमें 'चमक दमक' के बजाय सत्यजीत रे की धारणा के अनुसार 'विशिष्ट और भारतीयता की छाप' छोड़ने की कोशिश दिखायी दी। संयोग से, 'नीचा नगर' कान फ़िल्मोत्सव में सम्मान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय फ़िल्म बन गई। इसने 1946 में प्रथम कान फ़िल्म पुरस्कारों में कई अन्य फ़िल्मों के साथ सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का पुरस्कार प्राप्त किया। 1948 में, उदय शंकर की शालीन लेकिन कुछ हद तक अव्यवस्थित फ़िल्म 'कल्पना' ने दर्शकों के मनोरंजन के लिए अंतहीन नाच-गाने के बजाय भारतीय सिनेमा में नृत्य-संगीत को एक विधा के रूप में स्थापित करने की संभावनाएं खोलीं। हालांकि, भारत के लिए सफलता का सबसे बड़ा क्षण 1955 में स्वयं सत्यजीत रे फ़िल्म निर्माता के रूप में लेकर आये।

सत्यजीत रे की बांग्ला फ़िल्म 'पाथेर पांचाली' आज तक भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा मील का पत्थर है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी उपलब्धि है जो पहले भी और आज भी भारतीय फ़िल्मों को प्रोत्साहित करती है।

1950 के दशक में यकायक भारतीय फ़िल्मों को विदेशी फ़िल्मोत्सवों में प्रवेश मिलने लगा और काफी सराहा जाने लगा। 1957 में यह सिलसिला चरम पर पहुंच गया। सत्यजीत रे की दूसरी फ़िल्म, 'अपराजितो' (पाथेर पांचाली की अगली कड़ी) ने वेनिस फ़िल्मोत्सव में गोल्डन लायन और क्रिटिक्स पुरस्कार सहित कुल 11 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीते। दोनों पुरस्कार प्राप्त करने वाली यह पहली फ़िल्म थी। अमित मित्र और शम्भू

शोम' और मणि कौल की 'उसकी रोटी' ने 1969 में भारतीय सिनेमा में नई लहर की शुरुआत की। संयोग से, कौल फ़िल्म संस्थाान से स्नातक थे। इस संस्थान ने जल्द ही भारत को मणि कौल, कुमार शाहनी, अडूर गोपालकृष्णन, गिरीश कासरवल्ली जैसे कई साहसी और भावबोधक फ़िल्म निर्माता दिए जिन्होंने भारतीय सिनेमा की सीमाओं को विस्तार दिया। जब फ़िल्म सोसायटियां, दर्शकों का एक विशेष वर्ग तैयार कर रही थीं, उसी दौर में फ़िल्म संस्थान, तकनीकी प्रशिक्षण का ऐसा मंच बन गया था जिसका अब तक अभाव था। फ़िल्म वित्त निगम ने न केवल फ़िल्म संस्थान के स्नातकों बल्कि सिनेमा में कुछ अलग सौंदर्यमय अभिव्यक्ति के लिए प्रतिबद्ध अन्य फ़िल्म निर्माताओं के अनूठे प्रयासों के लिए भी धन उपलब्ध कराया।

इन तीनों संस्थाओं ने किसी सोची-समझी सहमति के बिना ही, 1969 के बाद से बांग्ला और हिंदी सिनेमा की छिटपुट तरंगों को राष्ट्रीय सिनेमा की उद्दाम लहर का रूप दे दिया। अब तक व्यावसायिक फ़िल्मों के जाल में उलझी अनेक अन्य भाषाओं में भी सार्थक फ़िल्में बनने लगीं। मराठी, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, असमिया और ओडिशा में नए किस्म के सिनेमा की धाक जमने लगी। उदाहरण के लिए, अरिबाम स्याम शर्मा की 'इमागी निंगथेम' (1981) ने पूर्वोत्तर भारत के सिनेमा को पहली बार विश्व मंच पर स्थापित किया।

70 के दशक के मध्य में, लोकप्रिय मुख्यधारा सिनेमा में 'एंग्री यंग मैन' का उदय हुआ, जो अपने और अपने जैसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए जूझ रहा था। 'अंडरवर्ल्ड' और 'गैंगस्टर्स' शब्दों ने भारतीय सिनेमा की शब्दावली में जगह बना ली। समय के साथ, 'मिस्टर इंडिया' (1987) के 'मोगैम्बो, खुश हुआ' से लेकर 'सत्या' (1998) में भीखू म्हात्रे के 'मुंबई का किंग कौन?' जैसे संवादों के साथ भारतीय मुख्यधारा सिनेमा ने कल्पना जगत से पराजगत तक का सफर तय कर लिया।

50 के दशक का सिनेमा बहुत हद तक गांवों से शहरों की ओर पलायन का प्रतीक था, उसी के साथ-साथ दशकों के इस सफर में भारतीय सिनेमा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ने लगा। सत्यजीत रे की 'महानगर' (1963) में अनिश्चितताओं से भरे जीवन से जूझती कामकाजी महिला से लेकर, बिमल रॉय की निम्न जाति की बेचारी 'सुजाता' (1959), 'उम्बर्था' (1982) में अधिक आत्मविश्वासी सावित्री या बाद में, 'क्वीन' (2014) में रानी के किरदार इसके उदाहरण हैं।

'द एलिफेंट व्हिस्पर्स' (2022) पहला भारतीय वृत्तचित्र है जिसने 95वें अकादमी पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ लघु फ़िल्म के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। दशकों से दुनिया भर में सबसे अधिक फ़िल्में बना रहे देश में, भौगोलिक क्षेत्र और भाषाओं के हिसाब से किसी रूझान को पहचान पाना कठिन काम है।

भारत में वृत्त चित्रों, लघु फ़िल्मों और एनीमेशन निर्माण में भी प्रगति का एक लंबा इतिहास रहा है।

पिछले पचहत्तर वर्षों में फ़िल्मों में राष्ट्रवाद का चित्रण भी बहुत होने लगा। आज़ादी से पहले और बाद में देशभक्ति की फ़िल्मों के अलावा, कुछ अन्य फ़िल्में, जैसे, 'मदर इंडिया' (1957) उभरते राष्ट्र में विकास के प्रयासों को चित्रित करना चाहती थीं। नई सहस्राब्दी में खेलों के माध्यम से देशभक्ति की भावना फिर जागृत हुई। 'लगान' (2001), 'चक दे! इंडिया' (2007) और प्रख्यात खिलाड़ियों के जीवन पर बनी फ़िल्मों ने समूचे देश के दर्शकों को आकृष्ट किया। ❑

नोट : चित्र लेखक की हालिया पुस्तक '75 साल 75 फ़िल्म्स' से ली गई है।

Elite Academy for Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
नवी मुंबई	701, सी-विंग, केन्द्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एस्प्लेनेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुवनंतपुरम	प्रेस रोड, गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बेंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2675823
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455

काला पानी

लेखक : हिमांशु जोशी

पृष्ठः 70, मूल्य : 105 रुपये

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. * Delhi *

काला पानी की सज़ा को भयावह दुःस्वप्न के रूप में देखा जाता है। वहां कैदियों को दी जाने वाली यातनाओं का विवरण रोंगटे खड़े कर देता है। अंग्रेज़ों ने भारत की मुख्य भूमि से सैंकड़ों मील दूर अंडमान द्वीप में सेलुलर जेल बनाई। अनेक स्वतन्त्रता सेनानियों को वहां घोर अमानवीय यातनाएं दी गईं। इस पुस्तक में इन यातनाओं का मार्मिक वर्णन किया गया है। पुस्तक के लेखक जाने-माने कथाकार हैं।

'काला पानी' का सांस्कृतिक भाव 'काल' से बना है जिसका अर्थ 'समय' या 'मृत्यु' होता है। 'काला पानी' शब्द का अर्थ मृत्यु के उस स्थान से है जहां से कोई भी वापस नहीं आता है। इस जेल में 15X8 फ़ीट की कुल 698 कोठरियां थीं। सभी कोठरियों में तीन मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बनाये गए थे ताकि कै़दी एक-दूसरे से बात न कर सकें। ऐसे में कै़दी बिल्कुल अकेले पड़ जाते थे और ये अकेलापन उनके लिए मौत से भी भयानक होता था।

वर्षों तक सभी कै़दी बाहर ही रहते थे घास-फूस की झोपड़ियों में, किन्तु बाद में एक पक्की जेल बनाई गई जो 1905 में पूरी हुई। इस जेल का नाम रखा गया- सेलुलर जेल। हर कै़दी को प्रतिदिन नौ घंटे कठोर काम करना अनिवार्य था। हर कै़दी को वर्ष में एक ही पत्र मिलता था और केवल एक ही पत्र इस अवधि में उसे भेजने की अनुमति थी। यदि अधिकारी चाहते तो इस सुविधा से भी उन्हें वंचित कर सकते थे। भोजन के नाम पर जो भी मिलता, उन्हें सब खाना पड़ता। कई बार भोजन करते समय सब्ज़ी में केंचुल के टुकड़े मिलते तो कभी-कभी सांप की बोटियां भी।

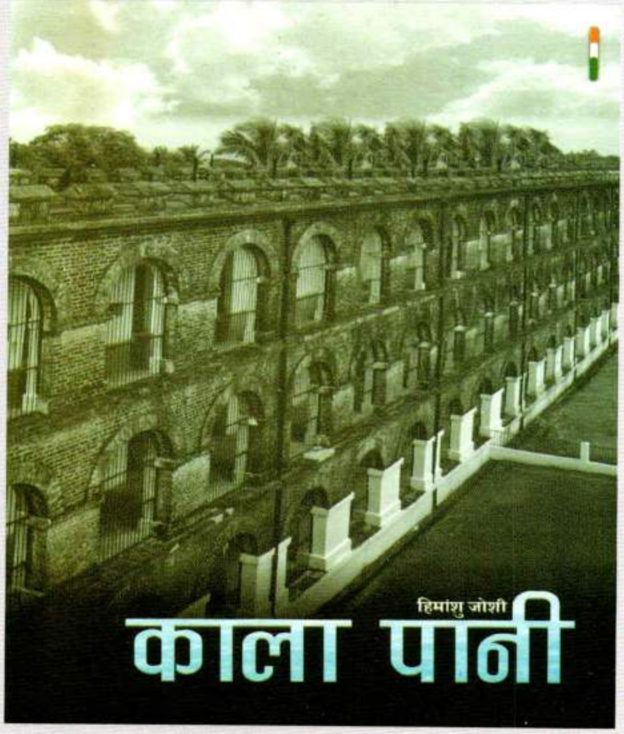

हमारे देश में समय-समय पर ऐसे वीर सपूत अवतरित हुए, जिनकी गौरव गाथाएं हमारे इतिहास का शृंगार बन गई हैं। आज़ादी की लड़ाई के परवाने कुछ ऐसे भी हैं, जिनके नाम शायद हमारे मानस पटल पर नहीं हैं। निष्काम भाव से त्याग करने वाले ऐसे कितने ही सेनानी हैं, जिन्होंने यातनाओं पर यातनाएं सहते हुए देश को परतन्त्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए निःस्वार्थ भाव से अपने प्राणों तक की आहुति दे डाली। ऐसे नींव के सशक्त पत्थरों पर ही राष्ट्र का भव्य भवन खड़ा है। सचमुच ऐसे वीरों का त्याग और बलिदान ही सच्चा त्याग है, जिनकी अमर कहानी 'काला पानी' की दीवारें आज भी कह रही हैं। उन वीरों को, अपने परिवार से बिछुड़कर, अंग्रेज़ी शासन में कैसी-कैसी घोर यातनाएं सहन करनी पड़ीं, उन्हें पढ़-पढ़कर रोम-रोम सिहर उठता है। जो गाथाएं एवं जो महान चरित्र हमारे प्रेरणा-स्रोत हैं, उन्हें आज सारा देश नमन करता है। सुपरिचित लेखक हिमांशु जोशी ने 'काला पानी' शीर्षक से अपनी इस पुस्तक में भारत माता के ऐसे वीर सपूतों- जिसमें वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, शचीन्द्रनाथ सान्याल, भाई परमानन्द, उपेन्द्रनाथ बनर्जी, ज्योतिषचन्द्र घोष, उल्हासकर दत्त, बाबा भानसिंह, वारीन्द्र कुमार घोष, पृथ्वी सिंह आज़ाद, नानी गोपाल, गोविन्द चरण जैसे गुमनाम क्रान्तिकारियों की अदम्य, साहसिक और देशभक्तिपूर्ण गाथाओं का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है।

सेलुलर जेल में आने वालों में अंतिम व्यक्ति थे - नेताजी सुभाष चन्द्र बोस। वह बंदियों के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वाधीन नागरिक, एक मुक्त योद्धा और एक विजेता सेनापति के रूप में इस द्वीप में आए। उन्होंने काला पानी के द्वीपों में तिरंगा फहराकर सेलुलर जेल के द्वार हमेशा के लिए खोल दिए।

वास्तव में ये स्वातंत्र्य वीर काले द्वीप में धधकते अंगारे थे, जिसकी ऐसी गौरव गाथाएं हमारे इतिहास के पृष्ठों में सदा दैदीप्यमान रहेंगी। ❑

ELITE IAS ACADEMY

General Studies Integrated (Offline)

1 Year

Features

- GS for Pre and Mains
- Lifetime Access of Class Recording
- Weekly Current Affairs Classes
- Essay Writing
- Pre and Mains Test Series
- On Demand Mentor Support
- Include CSAT

Registration Open

Demo Session

+91 7065202020,
8899999931/34 8410000036

info@eliteias.in